



Mkd iithdj.k l[;kj/RNP/01/2023-25

NRNI NO. UPHIN/2009/27689

राष्ट्रीय निष्पक्ष, निर्भीक हिन्दी दैनिक

जन विचार प्रवाह

वर्ष : 18 अंक :253

(हिन्दी दैनिक)

जौनपुर गुरुवार 01 अक्टूबर, 2026

पृष्ठ- 08

मूल्य- 2.00 रुपया

सीईसी ज्ञानेश कुमार को क्यों मिली कानूनी छूट? राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा तीखा निशाना

नई दिल्ली 30 सितम्बर (एजेंसी)लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को मुख्य चुनाव आ्युक्त (ब्) ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनावी नतीजों में हेरफेर करने के लिए उनका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। र पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार देश के एकमात्र ऐसे नागरिक हैं जिन्हें आजीवन पूरी कानूनी छूट मिली हुई है। गांधी ने कहा, फ्सवालरू ब्द ज्ञानेश कुमार एकमात्र ऐसे भारतीय क्यों हैं जिन्हें आजीवन पूरी कानूनी छूट मिली हुई है? जबावरू क्योंकि च्द मोदी चुनावों में धांधली करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं।कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि छक्क। गठबंधन के सभी नेताओं का यह पक्का वादा है कि हम यह पक्का करेंगे कि जिन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद किया है उन्हें सजा मिले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने सीनियर हैंया कैबिनेट हैंय भारतीय लोकतंत्र इस देश के हर व्यक्ति से बड़ है। उन्होंने कहा कि बैठक में यह भावना भी थी कि विपक्ष भारत के लोगों तक यह बात पहुँचाने में काफी सफल रहा है कि चुनाव में धांधली हुई है।

पीएम मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल की याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने बरकरार रखा 25 हजार का जुर्माना



नई दिल्ली 30 सितम्बर (एजेंसी)गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकारी पद पर बैठ्ा कोई राजनीतिक नेता अपने राजनीतिक हितों के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (।।च्) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने से जुड़े मामले में उन पर लगाए गए २25,000 के जुर्माने को चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रे की डिवीजन बेंच ने कहा अपीलकर्ता ने अपने खर्चिलाफ चल रही कार्यवाही में ब्द (सीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन) को जिस तरह कोई आदेश नहीं दिया गया है। स्टे (रोक) के लिए दी गई सिविल अर्जी भी खारिज कर दी जाती है। 2016 में गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रार के जरिए गुजरात हाई कोर्ट में ब्द के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी।

कोई और टिप्पणी या राय देने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने मार्च 2023 के उस सिंगल जज के आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें ब्द के 2016 के उस निर्देश को रद्द कर दिया गया था, जिसके तहत गुजरात यूनिवर्सिटी को मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी देनी थी। यूनिवर्सिटी ने ब्द के निर्देश को चुनौती देते हुए सिंगल जज का रुख किया था। ब्द का यह आदेश केजरीवाल की ओर से सूचना का अधिकार अधििनियम (रूज एक्ट) के तहत दी गई अर्जी पर जारी किया गया था।लाइव लॉ के अनुसार, डिवीजन बेंच ने कहा इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अपील करने वाले की किसी भी दलील में कोई गलती नहीं पाई गई है। इसलिए अपील खारिज की जाती है और खर्चा को लेकर भी कोई आदेश नहीं दिया गया है। स्टे (रोक) के लिए दी गई सिविल अर्जी भी खारिज कर दी जाती है। 2016 में गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रार के जरिए गुजरात हाई कोर्ट में ब्द के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी।



नई दिल्ली 30 सितम्बर (एजेंसी)प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने किसानों, अक्षय ऊर्जा और राजधानी दिल्ली की यातायात व्यवस्था से जुड़े तीन महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगा दी। बैठक मेंलिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि इन तीनों फैसलों से जुड़ कुल वित्तीय प्राक्ान 2 लाख 79 हजार 157 करोड़ रुपये का है। हम आपको बता दें कि बैठक में लिए गये फैसलों का सबसे सीधा असर किसानों पर पड़ने वाला है। मोदी सरकार ने रबी विपणन सत्र 2027–28 के लिए छह प्रमुख

फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय इस मूल्य व्यवस्था में उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत का लाभार्ध सुनिश्चित करने सहित लागत, फसलों के बीच आय का संतुलन, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतें मांग-आपूर्ति तथा कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापारिक संबंों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा गया है।

नई व्यवस्था के तहत गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,610 रुपये प्रति क्विंटल, जौ का 2,286 रुपये, चने का 5,958 रुपये, मसूर का 7,390 रुपये, सरसों का 6,613 रुपये और

ारा 354 के तहत दर्ज की गई थी। उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने निजी जगह में घुसकर उसे परेशान किया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, उसने आरोप लगाया कि उसने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन फिर भी थ्द किसी अज्ञात व्यक्ति के खर्चिलाफ दर्ज की गई। उसने आगे आरोप लगाया कि हाई कोर्ट द्वारा रिपोर्ट मांगने के बाद आरोपी का नाम मामले में शामिल किया गया और अंततः उसे क्लीन चिट दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई। उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील जिजेंद्र सिंह ने इस बात से इनकार किया कि कोर्ट ने राज्य पुलिस के खर्चिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी की थी। एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के अनुसार, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केवल याचिकाकर्ता की दलीलों पर ध्यान दिया था और UP पुलिस से हलफनामा मांगा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह कोर्ट के सामने इन आरोपों का जवाब देगी।

इधर विपक्षी गठबंधन इंडिया अपनी बैठक में व्यस्त रहा, उधर मोदी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लेकर देश को चौंका दिया

नई व्यवस्था के तहत गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,610 रुपये प्रति क्विंटल, जौ का 2,286 रुपये, चने का 5,958 रुपये, मसूर का 7,390 रुपये, सरसों का 6,613 रुपये और कुसुम का 7,215 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

कुसुम का 7,215 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार के अनुमान के मुताबिक रबी विपणन सत्र 2027–28 में 324 लाख मीट्रिक टन उपज के लिए किसानों को करीब 90,962 करोड़ रुपये का भुगतान अनुमानित है। दूसरा बड़ा फैसला अक्षय ऊर्जा के मोर्चे पर है। मंत्रिमंडल ने पीएम धारा योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत कुल 1 लाख 86 हजार 405 करोड़ रुपये का परियोजना व्यय होगा, जिसमें 54 हजार 82 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल है। योजना का उद्देश्य देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के साथ उसके लिए जरूरी पॉसेण व्यवस्था को मजबूत करना है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है जबकि 2035–36 तक 786 गीगावाट क्षमता की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत 135 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के पॉसेण और 50 गीगावाट-च्हे तीसरे चरण में 30 मागी पर 620 स्मार्ट यातायात बतियां लगाई जाएंगी। इस

एजेंसियां इसे लागू करेंगी। नई पॉसेण लाइनों का निर्माण प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए होगा, जबकि मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन के लिए लागत आधारित व्यवस्था अपनाई जाएगी तीसरा और दिल्ली से सीधे जुड़ फैसला एकीकृत यातायात प्रबंध प्रणाली को मंजूरी देा है। इसके लिए 1,790 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार के मुताबिक दिल्ली की 1,529 यातायात बतियां अभी निश्चित समय-सारिणी और मानवीय हस्तक्षेप पर निर्भर हैंतथा जाम बड़ने पर स्वतः प्रतिक्रिया नहीं दे पाती। नई व्यवस्था में यातायात नियंत्रण, नियमों का पालन, वास्तविक समय की यातायात जानकारी और मार्ग परिवर्तन को एक ही तकनीकी ढंव से जोड़ जाएगा।वह परियोजना 24 महीने में तीन चरणों में लागू होगी। पहले चरण में पांच मागी पर 250 स्मार्ट यातायात बतियां और मुख्य नियंत्रण केंद्र, दूसरे चरण मेंसात मागीपर 222 स्मार्ट यातायात बतियां तथा आपदा पुनर्प्रति व्यवस्था और तीसरे चरण में 30 मागी पर 620 स्मार्ट यातायात बतियां लगाई जाएंगी। इसके

बाद पांच वषातक रखरखाव किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित व्यवस्था यातायात उल्लंघनों की पहचान करने के साथ चेरी या वॉचित वाहनों की पहचान में भी मदद करेगी। इस तरह मेद्री सरकार के आज के फैसलों का फेफ़स किसान की आय, ऊर्जा ढंव के विस्तार और दिल्ली की यातायात व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर साफ तौर पर दिखाई देता है।

पूर्व पीएम शेरव हसीना ने बताया वापस आने की बात कहा-में बांग्लादेश लौटने की तैयारी कर रही हूं

नयी दिल्ली बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेरव हसीना ने एक बार फिर कहा है कि वह स्वदेश लौटने का इरादा रखती हैं। ब्रिटेन स्थित थिंक टैंक ग्लोबल सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नैसर् की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में वो वरुडुअल मोड में जुड़ीं। इस दौरान एक सवाल के जवाब में हसीना ने कहा, मैं बांग्लादेश वापस जाने की योजना बना रही हूं। सही वक्त आने पर मैं खुलासा कि क्या वो सी फीसदी इस बात पर कायम है कि इस साल दिसंबर में (जैसा उन्होंने पहले दावा किया था) बांग्लादेश लौटेंगी? हसीना ने कहा, जी बिल्कुल, मैं पक्का इरादा रखती हूं। सभी जानते हैं कि मेरा पासपोर्ट वगैरह सब सील हो गया है। मैं योजना बना रही हूं। सही वक्त आने पर मैं खुलासा करूंगी कि कैसे और कब मैं वहां जाने वाली हूं। उन्होंने अपने समावित वापसी को लेकर कहा है कि वे कानूनी परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनके मुताबिक, उनका बांग्लादेश लौटने का फैसला उनके देश और वहां के लोगों से जुड़ा है। वैसे पहली बार नहीं है कि निर्वासित जीवन जी रही हसीना ने बांग्लादेश लौटने की इच्छा जाहिर की हो। इससे पहले भी वो स्वदेश लौटने का ऐलान कर चुकी हैं। 5 अगस्त को दक्षिण एशिया के फॉरेन कॉरस्पोंडेंट्स क्लब (एफसीसी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी वो वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़ी थीं और यहां भी उन्होंने स्वदेश लौटने की इच्छा जताई थी। इस कार्यक्रम में उनके साथ उनके बेटे साजीब वाजेद जॉय और पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी नौफेल सहित अन्य अवामी लोग नेता भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा, "मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, मुझे जेल भेजा जा सकता है। लेकिन उर जनता के प्रति मेरे कर्तव्य को तय नहीं कर सकता। जब मेरे प्यारे देशवासी करंट ड्रेल रहे हों तो मैं चुप नहीं रह सकती।" तब भी वापसी की सही तारीख को लेकर उन्होंने कहा था कि समय आने पर घोषणा की जाएगी, लेकिन कानूनी पेचीदगियों का हवाला दे दावा किया कि वो इस साल दिसंबर में वहां जा सकती हैं। हसीना ने कहा था कि उनकी अवामी लोग पार्टी पर लगा प्रतिबन्ध हटा दिया जाना चाहिए। वहीं, उनके बेटे ने कहा था कि मौजूदा सरकार ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। वहीं, जुलाई में रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में भी हसीना ने कहा था कि वह दिसंबर में अपने वरिष्ठ पार्टी सहयोगियों के साथ बांग्लादेश लौटकर अदालत के सम्मक्ष आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं। पूर्व पीएम के खिलाफ बांग्लादेश में कानूनी मामले चल रहे हैं और उन्हें एक मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी है।

यूपी पुलिस के सभी केस सीबीआई को सौंप दें कुशीनगर बाढ़: जमीनी हालात पर सीएम योगी पीड़ितों को राहत सामग्री, 10 दिनों में फसल का मुआवजा

अज्ञात पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की पहचान पता होने के बावजूद अज्ञात व्यक्तिके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने सवाल जताया कि इस तरह के आचरण से लोग पुलिस पर कैसे भरोसा करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्रशासन को इस मामले में नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।



नई दिल्ली 30 सितम्बर (एजेंसी)सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को आरोपी की पहचान पता होने के बावजूद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करने पर कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने सवाल किया कि ऐसे हालात में लोग पुलिस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, और सुझाव दिया कि राज्य में सभी आपराधिक मामलों की जांच CBI को सौंप दी जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह राज्य की पूरी पुलिस फोर्स को ही भंग कर सकती है। कोर्ट ने

ुई कोर्ट ने देखा कि UP पुलिस के हलफनामे में ही आरोपी का नाम बताया गया था। यह जानकारी होने के बावजूद, कथित तौर पर FIR में उसका नाम नहीं लिखा गया। कोर्ट ने इस पर सख्ती से जवाब मांगा। कोर्ट ने UP प्रशासन को FIR से जुड़े हालात बताते हुए एक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि निर्देशों का पालन करना एक बात है, लेकिन संबंधित आचरण को बचाने या छिपाने के लिए इतनी दूर तक जाना मंजूर नहीं है। यह मामला एक महिला से जुड़ा है जिसने आरोपी को मिली अग्रिम जमानत को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आरोपी को शुरू में निचली अदालत ने जमानत दे दी थी। इसके बाद महिला ने उसकी जमानत रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी याचिका ठुकरा दी। इसके बाद उसने हाई कोर्ट के आदेश के खर्चिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। घ्मूल मामले में उसकी शिकायत प्च की ६

ारा 354 के तहत दर्ज की गई थी। उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने निजी जगह में घुसकर उसे परेशान किया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, उसने आरोप लगाया कि उसने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन फिर भी थ्द किसी अज्ञात व्यक्ति के खर्चिलाफ दर्ज की गई। उसने आगे आरोप लगाया कि हाई कोर्ट द्वारा रिपोर्ट मांगने के बाद आरोपी का नाम मामले में शामिल किया गया और अंततः उसे क्लीन चिट दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई। उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील जिजेंद्र सिंह ने इस बात से इनकार किया कि कोर्ट ने राज्य पुलिस के खर्चिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी की थी। एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के अनुसार, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केवल याचिकाकर्ता की दलीलों पर ध्यान दिया था और UP पुलिस से हलफनामा मांगा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह कोर्ट के सामने इन आरोपों का जवाब देगी।



ताकि नदी ज़्यादा पानी को बेहतर ढंग से बहा सके। आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों का भी जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और उन्हें हर जरूरी मदद दी जाए। उन्होंने अधिकारियों से नारायणी नदी से हुए नुकसान और तटबंध मेंआई दरार के बारे में जानकारी मांगी।मुख्यमंत्री ने विस्थापित परिवारों से बातचीत की और ऊंचे स्थानों पर ठहराए गए लोगों को जरूरी राहत सामग्री बांटी, जिसमें चावल, आटा, दाल और आलू जैसी खाने की मुख्य

नैनात की गई है। संकट की इस घड़ी में त्थ्रच सरकार उन सभी लोगों के साथ खड़ी है जो इससे प्रभावित हुए हैं। प्रभावित परिवारों को मदद मिलनी शुरू हो गई हैय हमने 10 किलो चावल, आटा और आलू के साथ-साथ 2 किलो दाल और अन्य सामान भी उपलब्ध कराए हैं।

अनुग्रह राशि और मुआवजे का

ऐलान कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए योगी ने घोषणा की कि बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिवारों को 4–4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के घर बारिश और बाढ़ के कारण पूरी तरह नष्ट हो गए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नए घर दिए जाएंगे, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फसल के नुकसान का आकलन पूरा करने और प्रभावित किसानों को 10 दिनों के भीतर मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए 5,000 खाने के पैकेट का ईंटजाम किया है, जिनमें चावल, आटा, आलू, दाल, चना, तेल, मसाले, नमक और दूसरी जरूरी चीजें शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सुरक्षित जगहों पर ले जाए गए लोगों को तुरंत राहत कैंपों में पहुंचाया जाए और कैंपों में रेशन की उचित इंटजाम किया जाए।वर्तमान में देखे को पूरी सरकार संकट की इस घड़ी में प्रभावित लोगों के सहयोग के लिए खड़ी है। जनप्रतिनिधि भी राहत और बचाव कार्य में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। मंत्री से लेकर अधिकारी तक पहुंच रहे हैं।

अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग को लेकर वकीलों ने किया न्यायिक कार्यों से किनारा



बांदा। अधिवक्ताओं की सुर्क्षा और विभिन्न मांगों को लेकर जनपद के वकीलों का आक्रोश बुधवार को खुलकर सामने आ गया। सुर्क्षा कानून बनाए जाने की मांग को लेकर बुवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से पूरी तरह विरत रहे और कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष विमल कुमार सिंह के नेतृत्व में वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी अमित असेरी से मिला और उन्हें अपनी समस्याओं व मांगों से अवगत कराया। जिलाध्यक्ष विमल कुमार सिंह ने सरकार और प्रशासन के सम्मक्ष कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अधिवक्ता समाज को न्याय दिलाने का पवित्र कार्य करता है, लेकिन विडंबना यह है कि आज अधिवक्ता खुद पूरी तरह असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि जब तक प्रदेश और देश स्तर पर अदि वक्ताओं की सुर्क्षा को लेकर कड़ा इधिवक्ता सुर्क्षा कानूनस पास नहीं किया जाता, तब तक वकीलों का यह संघर्ष और प्रदर्शन इसी प्रकार जारी रहेगा। अदि वक्ताओं के न्यायिक कार्यों से विरत रहने और हड़ताल पर जाने के कारण कचहरी और आदालतों में कामकाज ठप रहा, जिससे दूर-दराज से आए वादकारियों को बैरंग लौटना पड़ा। वकीलों ने एक स्वर में मांग की है कि अदि वक्ताओं पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए सरकार तत्काल प्रभाव से सुर्क्षा कानून लागू करे। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

बाजार से गलियों तक चलेगा विशेष सफाई अभियान, डीएम ने दिए व्यापक सफाई के निर्देश



धार्मिक स्थलों, चौराहों, नालियों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई के साथ कचरे का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश उरई (जालौन)जिलाधिकारी समीर ने कलेक्ट्रेट सभागार से जनपद के समस्त नगर निकायों एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों के साथ वर्युअल समीक्षा बैठक कर विशेष सफाई अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान को पूरी गंभीरता और व्यापकता के साथ चलाया जाए, ताकि नगरीय क्षेत्रों में कहीं भी गंदगी दिखाई न दे और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित हो सके। जिलाधिकारी ने बाजारों, धार्मिक स्थलों, मुख्य मार्गों, चौराहों, नालियों, सार्वजनिक स्थलों तथा महापुरुषों की मूर्तियों के आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल प्रमुख स्थानों तक ही अभियान सीमित न रहे, बल्कि भीतरी एवं अवासीय क्षेत्रों की गलियों में भी व्यापक स्तर पर साफ-सफाई कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के दौरान उपलब्ध सभी आवश्यक संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जाए तथा सफाई के बाद एकत्रित कचरे का निर्धारित नियमों एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सफाई कार्य की नियमित निगरानी करने तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि अभियान का वास्तविक प्रभाव वरातल पर दिखाई दे। जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष सफाई अभियान को जनभागीदारी से और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसी क्रम में यदि किसी वार्ड, मोहल्ले अथवा क्षेत्र में सफाई नहीं हुई है या कहीं गंदगी पड़ी है तो आम नागरिक इसकी सूचना देकर प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं। नागरिक मोबाइल नंबर 9936256363 पर फोन कर अपने क्षेत्र की सफाई संबंधी जानकारी दे सकते हैं, ताकि संबंधित अधिकारी को तत्काल अवगत कराकर आवश्यक कार्रवाई एवं सफाई सुनिश्चित कराई जा सके। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किए जा रहे सफाई कार्यों और उसके परिणामों को जनसामान्य तक पहुंचाया जाए, जिससे नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़े और स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ नगरीय वातावरण के निर्माण में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो।

अपहरण, दुष्कर्म व पावसो एक्ट का वाछित अभियुक्तगिरफ्तार

शाहजहापुर। थाना मिर्जापुर पुलिस ने नाबालिग अपहृता के अपहरण, दुष्कर्म और पावसो एक्ट के वाछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। 10 सितम्बरको एक ब्यक्ति ने थाना मिर्जापुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को गांव कम्परपुर का रहने वाला सुदेश उर्फ सिद्धू बहल-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार आरोपी सुदेश उर्फ सिद्धू के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया और तत्काल कार्रवाई करते हुए अपहृता किशोरी को बरामद किया। पुलिस ने पीछ्तिता के मंडिकल और बयानों के आधार पर अभियोग में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की बढ़तेरी की। आज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सुदेश उर्फ सिद्धू को मिर्जापुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर उसे न्यायालय के सम्मक्ष पेशकर जेल भेज दिया है। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में मिर्जापुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार के साथ उपनिरीक्षक मोहम्मद फरमान, हेड कार्टेबल रणवीर सिंह आदि मौजूद रहे।

नवांगत बीईओ का शिक्षक संघ ने किया स्वागत

फतेहपुर। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ हसवा इकाई ने बुधवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र हसवा में नवांगत खंड शिक्षा अधिकारी किशन कुमार का पुष्पगुच्छ भेंटकर एवं मिष्ठान खिलाकर स्वागत किया। शिक्षकों ने विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार और योजनाओं के संचालन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को लेकर बीईओ के साथ विस्तार से चर्चा की।

बैठक में निपुण भारत मिशन को हसवा ब्लॉक में प्रभावी ढंग से लागू कर इसे अग्रणी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। शिक्षक संघ ने शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन व विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में अजब हाल!

-जहाँ होना या छात्राओं का बसेरा, वहाँ बँध रहीं भैसें, 3 दिन से छात्रों का उग्र अनशन

बांदा। पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में व्याप्त अय्यवस्थाओं और कथित घोर लापरवाही के चलते छात्रों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े करीब आधा सैकड़ा छात्र-छात्राएं कॉलेज गेट पर तंबू गाड़कर लगातार तीसरे दिन भी क्रमिक अनशन पर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए एक ऐसा सनसनीखेज आरोप लगाया है, जिसने महकमें में हड़कंध मचा दिया है। छात्रों का सबसे गंभीर और चौंकाने वाला आरोप महिला छात्रावास की बदहाली को लेकर है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, कॉलेज परिसर में महिला छात्रावास का निर्माण हुए 15 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक एक भी छात्रा को इसका आवंटन नहीं किया गया। नतीजा यह है कि करोड़ों की लागत से बना यह बहुमूल्य भवन



छात्राओं के सुरक्षित आश्रय की बजाय कथित तौर पर मवेशियों (भैंसों) का ठिकाना बन गया है। छात्रों ने तंज कसते हुए कहा कि यह भवन अब छात्रावास कम और मवेशियों का तबेला ज्यादा नजर आ रहा है। आंदोलित छात्रों ने खेल सुविधाओं पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा हर छात्र से खेल मद के नाम पर करीब 250 रुपये वसूले जाते हैं, इसके बावजूद परिसर में न तो पर्याप्त खेल सामग्री है और न ही खेलकूद की कोई बुनियादी सुविधा। छात्रों ने इस मद से की गई वसूली और उसके व्यय का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग

बांदा-फतेहपुर मार्ग बना हादसों का अड़्डा ’ पानी से भरे गहरे गड़ढे में पलटी ईंटों से भरी ट्राली -3000 ईटें बिखरीय बड़ा हादसा टला

तिंदवारीध्बांदा। बांदा-फतेहपुर मार्ग की बदहाली अब राहगीरों और वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित होती जा रही है। सड़क पर बने बड़े-बड़े और गहरे गड्ढे बारिश के पानी से लबालब भरकर अदृश्य खतरा बन चुके हैं। हालात यह हैं कि सड़क कहां है और गड्ढा कहां, यह पहचान पाना नामुमकिन हो गया है। इसी लापरवाही की बानगी गुरुवार सुबह तब देखने को मिली जब एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पानी से भरे गहरे गड्ढे में फंसकर पलट गई। घटना गुरुवार सुबह करीब पाँच बजे की है। विकास गैरेज के सामने बहुआ से बांदा की ओर आ रही ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक एक गहरे गड्ढे में जा धंसी। चालक देवेन्द्र ने बताया कि बारिश के पानी से भरा होने के कारण गड्ढा दूर से दिखाई नहीं दिया। जैसे ही ट्रॉली का पहिया उसमें उतरा, वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। इस हादसे में ट्रॉली में लदी करीब 3000 ईटें सड़क पर बिखर गईं। इनमें से बड़ी संख्या में ईटें टूटकर नष्ट हो गईं, जिससे लगभग 20 हजार रुपये के नुकसान का अनुमान है। गनीमत यह रही कि पलटते समय चालक ट्रॉली की चपेट में आने से बाल-बाल बच गया, वरना कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। बांदा-फतेहपुर मार्ग पर जगह-जगह बने गड्ढे लंबे समय से सिरदर्द बने हुए थे, लेकिन बारिश के बाद स्थिति और भी भयावह हो गई है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए तो यह मार्ग किसी खंदक से कम नहीं है। कार्यानक गड्ढे में पहिया जाने से वाहन फिसल रहे हैं और लोग रोज चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोग राहगीरों में लोक निर्माण विभाग की कायंशैली को लेकर भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि कागजी खानापूती और गड्ढों में सिर्फ मिट्टी डालने से समस्या हल नहीं होगीय सड़क की तत्काल स्थायी मरम्मत की आवश्यकता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन और जिम्मेदार विभाग किसी गंभीर और बड़ी दुर्घटना के इंतजार में हैं, या फिर समय रहते इस मार्ग की सुध ली जाएगी?

यमुना पर पक्के पुल की मांग को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा -डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन और सौंपा ज्ञापन



बांदा। तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र के जसपुरा ब्लॉक अंतर्गत यमुना नदी किनारे बसे तिरहार क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपनी वर्षों पुरानी मांग को लेकर बुवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार

हंकार भरी। मझौली कला, सबहदा और महबरा समेत कई गांवों के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को संबोधि त ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा।

संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का आगाज ’ आज से चलेगा विशेष अभियान, प्रशासन ने कसी कमर



बांदा। जनपद में संचारी रोगों पर प्रभावी रोकथाम और जन-जागरूकता को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बुधवार, 30 सितंबर 2026 को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की द्वितीय जनपद स्तरीय अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, जनपद में संचारी

रोग नियंत्रण अभियान 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक और दस्तक अभियान 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाया जाएगा। इस महाअभियान में 13 विभाग मिलकर समन्वित रूप से कार्य करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष फोकसरु ब्यू महोदय ने जिला पंचायत राज अडि।कारी को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित ब्लॉकों/कृजसपुरा, तिन्दवारी और बबेरुकूम प्रार्थमिकता के आधार पर लार्वा निरोधक दवाओं का छिड़काव

ग्रामीणों ने मांग की है कि यमुना नदी पर मझौली कला से पक्के पुल का निर्माण जल्द कराया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि यमुना नदी पर पक्के पुल के अभाव में उन्हें रोजाना गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासकर बरसात के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ने पर संपर्क पूरी तरह टूट जाता है या लंबी दूरी तय कर दूसरे रास्तों से आना-जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की भारी बर्बादी होती है। तिरहार क्षेत्र के ये गांव यमुना के किनारे बसे हैं, जहाँ के हजारों लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार और जिला मुख्यालय से संपर्क के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। पुल

न होने के कारण क्षेत्र का संपूर्ण विकास भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि शासन और प्रशासन ने जल्द से जल्द पुल निर्माण की घोषणा नहीं की, तो वे उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी यह मांग पूरी नहीं होती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस गंभीर समस्या को शासन स्तर तक पहुँचाकर निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए।

किया जाए और जलमराव का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हो। विद्यालयों की प्रार्थना सभाओं में बच्चों को संचारी रोगों से बचाव व साफ-सफाई की जानकारी दी जाएगी। साथ ही पेंटज, निबंध प्रतियोगिताओं और शुद्ध पेयजल के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। सभी ग्राम पंचायतों में नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई, एटी लार्वा छिड़काव, जलमराव निस्तारण और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए सभी एडीओ पंचायत को जवाबदेह बनाया गया है। स्वास्थ्य एवं बाल विकास पुष्टाहार विभागरु आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां घर-घर जाकर 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाले घरों पर संचारी रोग बचाव का स्टीकर लगाएंगी। पंपलेट्स बांटेंगी और मच्छर पनपने की स्थितियों को नष्ट करने की जानकारी देंगी। साथ ही, कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण कर पुष्टाहार दिया जाएगा। बुखार, खांसी-जुकाम और क्षय रोग के लक्षणों वाले मरीजों की सूची तैयार कर यूडीएसपी पोर्टल

पर अपलोड की जाएगी और आपातकाल में 108 एम्बुलेंस के उपयोग हेतु प्रेरित किया जाएगा। नगर पालिका व नगर पंचायतों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन साफ-सफाई, कूड़ा निस्तारण, नालियों की सफाई, फॉगिंग और लार्वा रोधी दवाओं का छिड़काव किया जाएगा। सुअर पालकों को संचारी रोगों से बचाव के प्रति संवेदीकृत त किया जाएगा तथा चूहा एवं छछूंर से फैलने वाले 'स्क्रब टाइफस' रोग के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजेन्द्र सिंह, समस्त अपररूप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डब्ल्यूएचओ के एसएमओ डॉ. जय नारायण, जिला मलेरिया अधिकारी श्रीमती पूजा अहिरवार, सहायक मलेरिया अधिकारी विजय बहादुर, जिला वेक्टर जनित रोग सलाहकार प्रिदा कुमार सहित शिक्षा, आईसीडीएस, नगर विकास, पशुपालन, कृषि और जल संस्थान विभागों के विभागाध्यक्ष एवं प्रमारी चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे।

नगर पंचायत अनपरा के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों को गति देने के लिए चेयरमैन विश्राम प्रसाद ने किया भूमि पूजन



अनपरा (सोनभद्र)। नगर पंचायत अनपरा के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों को गति देते हुए बुधवार को मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत स्वीकृत सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्यों का विधिवत भूमि पूजन कर शुभारंभ किया गया। नगर पंचायत के वार्ड संख्या 19 लक्ष्मीनगर रेणुसागर के बाद 03, 13 एवं 14 में प्रस्तावित निर्माण कार्यों का भूमि पूजन नगर पंचायत अध्यक्ष विश्राम प्रसाद बैसवार, रंजन यादव भाजपा मनोनीत सभासद रविजीत सिंह कंग एवं संबंधित वार्डों के सभासदों ने किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के माध्यम से नगर क्षेत्र में सड़क और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सीसी रोड एवं नाली निर्माण से स्थानीय लोगों को आवागमन के साथ ही जल निकासी की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। भूमि पूजन कार्यक्रम में संबंधित वार्डों के सभासदों के अलावा स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। विकास कार्य शुरू होने पर लोगों ने प्रसन्नता जताते हुए निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से पूरा कराने की अपेक्षा व्यक्त की।

औचक निरीक्षण में गैरहाजिरी पर सरस्वी, एक दिन का वेतन रोककर मांगा स्पष्टीकरण



उरई (जालौन)। जिलाधिकारी समीर के निर्देशन में बुधवार को जनपद के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों ने विकास भवन, लोक निर्माण विभाग, एआरटीओ, विद्युत तथा शिक्षा विभाग के कार्यालयों का निरीक्षण कर कर्मचारियों की उपस्थिति, अभिलेखों, लॉबित प्रकरणों, साफ-सफाई एवं जनसुविधाओं की स्थिति जांची विकास भवन स्थित कृषि, एनआरएलएम, सहकारिता, पशुपालन, ग्रामीण अभियंत्रण, डीआरडीए, डूडा, नेडा, लघु सिंचाई, जिला विकास अधिकारी एवं जिला अर्थ एवं संस्थाधिकारी कार्यालयों में कई अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित मिले। कुछ कर्मचारियों के अवकाश अथवा विभागीय कार्य से बाहर होने की जानकारी दी गई, जबकि कुछ मामलों में उपस्थिति पंजिका और प्रार्थना पत्र पंजिका में अंतर पाया गया। बिना पूर्व सूचना अथवा स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने के साथ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यालयों में भी अनुपस्थित कर्मचारियों के संबंध में जानकारी ली गई। एआरटीओ कार्यालय में तीन कर्मचारी बिना पूर्व सूचनास्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित मिले। कार्यालय में महत्वपूर्ण पुरानी पत्रावलियां खुले में मिलने तथा साफ-सफाई की स्थिति खराब पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अभिलेखों को सुरक्षित रखने और व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए गए। जनता से बातचीत में सर्वर समस्या एवं सूचना पट्ट के अभाव की शिकायत पर भी आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग के दोनों कार्यालयों के निरीक्षण में उपस्थिति एवं व्यवस्थाओं की जांच की गई। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पेशन एवं जीपीएफ तथा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पुरानी ऑफलाइन शिकायतें लंबित मिलीं। संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण अभियान के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालयों में समयबद्ध उपस्थिति, अभिलेखों का सुरक्षित रख-रखाव, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण और आमजन को सुचारु सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

एनटीपीसी के कमल नाथ ठाकुर आईसीएमएआई के आईएणएसबी बोर्ड के सदस्य मनोनीत



गाजियाबाद। गाजियाबाद में निवासरत एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान महारत्न कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड में सेवारत अपर महाप्रबंधक (वित्त) कमल नाथ ठाकुर को द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द इंटरनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेस स्टैंडर्ड बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। श्री ठाकुर वर्तमान में एनटीपीसी के कॉर्पोरेट आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग में कार्यरत हैं। उन्हें फाइनेंस एंड आंतरिक लेखा परीक्षण में तीन दशक से अधिक का अनुभव है। श्री ठाकुर को वर्ष 2024 में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'बेस्ट सीएमए अचीवर अवॉर्ड' से भी सम्मानित किया जा चुका है। आई ए ए एस बी बोर्ड के सदस्य के रूप में श्री ठाकुर आंतरिक लेखा परीक्षा और आश्वासन मानकों को मजबूत करने, पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में अपने अनुभव से संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे।

समाजवादी पार्टी के प्रो० रामगोपाल यादव और श्री धनराज परिमल नाथवानी ने विधानसभा भवन पहुंचकर राज्य सभा सदस्य के लिए नामांकन पत्र भरा



लखनऊ। राज्यसभा चुनाव के लिए आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रो० रामगोपाल यादव और श्री धनराज परिमल नाथवानी ने विधानसभा भवन पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव समेत समाजवादी पार्टी के विधायक एवं प्रमुख नेता मौजूद रहे

जन विचार प्रवाह



शहीद—ए—आजम सरदार भगत सिंह उस जेनजी के लिए ज्यादा प्रासंगिक हैं जिसकी ताकत तो इस देश ने देख ली लेकिन उसकी मुक्त परस्ती भी देखना बाकी है। दिल्ली के अंतर—मंतर पर जेनजी का आंदोलन परीक्षा और नौकरी तक ही सीमित था लेकिन देश को नयी सोच देकर विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा करने के लिए मुक्तपरस्ती भी दिखानी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश और देश के नाम पर अपनी पाती लिखते रहते हैं।

सम्पादकीय जल के लिए सहयोग

जल हमें उन तरीकों से जोड़ता है, जिनमें बहुत कम अन्य संसाध्ान जोड़ पाते हैं। नदियाँ प्रशासनिक सीमाओं को नहीं पहचानतीं। भूजल के स्रोत कई समुदायों की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। आज होने वाली बारिश कल पीने के पानी, सिंचाई, भूजल या नदी के प्रवाह का आधार बनती है।इससे एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता हैरू जल एक साझा संसाधन है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखना हमारी साझा जिम्मेदारी है। इसी भावना के साथ भारत 22 से 26 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ७वें भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह में वैश्विक जल समुदाय का स्वागत करेगा। इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय कर रहा है।

इस वर्ष की थीम है—जलवायु के प्रति लचीला जल प्रबंधन। जलवायु परिवर्तन के कारण जल चक्र लगातार अनिश्चित होता जा रहा है। ऐसे समय में यह विषय विशेष रूप से प्रासंगिक है। भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह केवल एक सम्मेलन नहीं है। यह ऐसा मंच है, जहाँ सरकारें, विशेषज्ञ, उद्योग जगत, समुदाय और अंतरराष्ट्रीय साझेदार अपने अनुभव, तकनीक और विचार साझा कर सकते हैं तथा भविष्य के लिए साझेदारियाँ बना सकते हैं। इसका उद्देश्य जल क्षेत्र से जुड़े हालिया विभागीय शिखर सम्मेलन की भावना और उससे मिली सीख को भी आगे बढ़ाना है। इस सम्मेलन का विचार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रखा था। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने एक साथ आकर जल क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा की, अपने अनुभव साझा किए और आगे की राह तय करने पर विचार—विमर्श किया। भारत इस संवाद में बड़े स्तर पर जल और स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं को लागू करने का व्यापक अनुभव लेकर आया है। प्र्धानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण भारत में 1५.9 करोड़ से अधिक घरों तक नल से पानी पहुँचाया गया है। वर्ष 2०19 में ऐसे घरों की संख्या 3.23 करोड़ थी। जल जीवन मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य जलापूर्ति के बुनियादी ढाँचे को भरोसेमंद सार्वजनिक सेवा व्यवस्था में बदलना है। इसके तहत ग्राम पंचायतों और उनकी ग्राहक जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) को ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति सेवाओं के संचालन, रखरखाव और निगरानी के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। इन्हें स्थानीय स्तर पर छोटी जल सेवा इकाइयों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

रजल सेवा आकलनछ ग्राम पंचायत के नेतृत्व में की जाने वाली एक डिजिटल पहल है। इसके तहत हर घर जल वाले गाँवों में पीने के पानी की नियमितता, पर्याप्तता, गुणवत्ता और स्थिरता का आकलन किया जाता है। यह पहल बुनियादी ढाँचा तैयार करने से आगे बढ़कर लगातार बेहतर जल सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इसमें जनभागीदारी के माध्यम से ग्राम पंचायतों और गाँव की संस्थाओं को आकलन की प्रक्रिया के केंद्र में रखा गया है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के माध्यम से भारत ने गंगा और उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें सीवेज से जुड़े बुनियादी ढाँचे और प्रदूषण कम करने के प्रयासों के साथ—साथ नदी के पर्यावरण को बहाल करने, जैव विविधता के संरक्षण और लोगों की भागीदारी पर भी ध्यान दिया गया है।इस कार्यक्रम के तहत ५27 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 3६7 पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से प्रतिदिन 4,२६3 मिलियन लीटर सीवेज के शोधन की क्षमता तैयार की गई है।

स्वच्छ भारत मिशन—ग्रामीण से भी एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे केवल बुनियादी सुविधाओं का विस्तार ही नहीं हुआ, बल्कि हमारी माताओं और बहनों को सम्मान मिला है और लोगों के व्यवहार में बदलाव सुनिश्चित करने में भी मदद मिली है। इस मिशन के दूसरे चरण में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन पर भी ध्यान दिया गया है। इसके तहत घरों और सामुदायिक स्तर पर इस्तेमाल के बाद निकलने वाले पानी यानी ग्रे—वॉटर के प्रबंधन के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।इन सभी योजनाओं में एक बात समान है—रजनभागीदारीछ। इसके पीछे यह विश्वास है कि सरकारी नीतियाँ तब सबसे अधिक प्रभावी होती हैं जब लोग केवल योजनाओं के लाभार्थी न रहकर उनके सक्रिय भागीदार बनते हैं।जल संरक्षण के हमारे प्रयासों में भी यही दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। रजल संवय जनभागीदारीछ और श्कैच द स्नेछ (वर्षा जल संवयन) जैसे अभियानों के माध्यम से हमारा उद्देश्य जल संरक्षण को केवल सरकारी योजना तक सीमित न रखकर लोगों की आदत और जनअंदोलन बनाना है।जलवायु के अनुकूल जल प्रबंधन तभी सफल हो सकता है, जब स्थानीय लोग इसे समझें इसे अपनी जिम्मेदारी मानें और इसे लंबे समय तक बनाए रखें। हाल ही में हमने श्वैच द स्नेछ अभियान का गीत भी जारी किया है।भारत के अनुभव से यह भी सीख मिलती है कि जल संबंधी चुनौतियों का कोई एक समाधान नहीं हो सकता। हिमालयी राज्य की जरूरतें किसी सूखे क्षेत्र से अलग होती हैं।

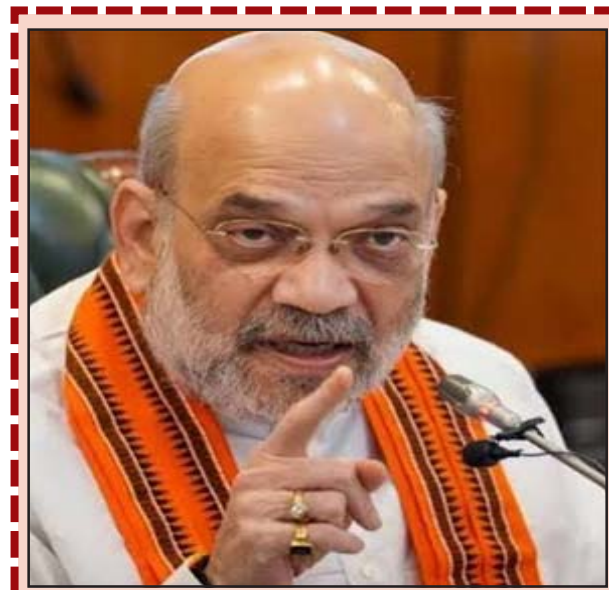
है। उन्होंने लिखा कि भगत सिंह ने परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। पाती में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जाति—पाति, नशा और अन्य सामाजिक बुराइयों की बेड़ियों से मुक्ति के लिए भगत सिंह के अदम्य साहस और राष्ट्रनिष्ठा से सीख लेनी होगी। सीएम योगी ने लिखा कि भगत सिंह अध्येता थे और हिंदी, उर्दू, पंजाबी एवं अंग्रेजी सहित कई भाषाओं के ज्ञाता थे। उनके जीवन से ज्ञान को अपनी शक्ति बनाने, सीखने की ललक को जीवित रखने और संकल्प को कर्म से जोड़ने की प्रेरणा मिलती है।

पाती में मुख्यमंत्री ने लिखा कि ज्ञान जब कौशल से जुड़ता है तो युवा अपनी प्रतिभा को सामर्थ्य में बदलकर अपने सपनों को साकार कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, उद्यम और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सहयोग दे रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री अम्युदय योजना के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क तैयारी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के जरिए उद्यम स्थापित करने और रोजगार

कृतज्ञता का महापर्व है श्राद्धतर्पण

ह्ककतीय सनातन पद्धतियाँ कृतज्ञता ज्ञापक हैं इसलिये भारतीय मानस देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, नरस्पति आदि के प्रति कृतज्ञता का बोध रखता है। किसी के द्वारा किये गए उपकार, सहयोग आदि को न भूलना एवं उसको स्मरण रखते हुये उसके प्रति आभार प्रकट करना भारतीय जीवन—शैली है। इसी भाव का प्रत्यक्ष उदाहरण है— श्राद्ध पक्ष। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक के 1६ (सोलह) दिन प्रत्येक वर्ष श्राद्ध के माने गये हैं। इस बार आश्विन कृष्ण नवमी तिथि की हानि होने से पितृ पक्ष 14 दिनों का होगा ०1अक्टूबर को मध्यान्ह में पंचमी व अपरान्ह में षष्ठी का भी श्राद्ध कर दिया जायेगा। विद्वानों का मत है कि आश्विन कृष्ण पक्ष की मान्यता पितृ पक्ष की है। शास्त्रीय विधान है कि आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा उदयतिथि में जिस दिन मिलती है उसी दिन से पितृपक्ष आरम्भ होता है। अतः अबकी पितृपक्ष का आरम्भ 27 सितम्बर 2026 दिन रविवार से प्रारम्भ हुआ जो 1० अक्टूबर 2026 दिन पनिवार को सर्वपत्री अमावस्या पर पितृ विसर्जन से समाप्त होगा। पूर्णिमा का श्राद्ध 26 सितम्बर को किया गया। तर्पण काल व श्राद्ध का समय मध्यान्ह में होना आवश्यक होता है।भारतीय मनीषियों ने अपनी तत्वानुवेष्टी मेधा एवं सूक्ष्मदर्शी संस्रुति सभ्यता एवं परम्परा को

है जो कि पितरों के निमित्त किया जाने वाला एक महा कर्तव्य है। पूर्वजों की अपूर्व ,पा से ही आज हम सब जीवित है। यह पूर्वजों का स्मृति समारोह है कर्तव्य बोध का प्रेरक है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि “अपनी वैज्ञानिक शोधों से मानव पर



भारत में आतंकवाद और सीमा पार से होने वाली आपराध्िक गतिविधियों के खिलाफ सुस्खा एजेंसियों की कार्यवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से जुड़े शहजाद भट्टी नेटवर्क के 40 से अधिक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है और देश के 15 राज्यों में इस नेटवर्क से जुड़े 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस नेटवर्क पर हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की

सृजित करने एवं स्टार्टअप नीति के जरिए नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिए जाने का जिक्र किया। उन्होंने योगी की पाती में युवाओं से उत्तर प्रदेश में उपलब्ध ज्ञान के साधनों का अधिक से अधिाक सदुपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा कि प्रदेश में भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर प्रत्येक जनपद में आधुनिक पुस्तकालय एवं डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की जा रही हैं, ताकि ज्ञान तक पहुंच सहज हो।मुख्यमंत्री ने युवाओं से पुस्तकों को अपना मित्र बनाने, प्रश्न पूछने, नए विचारों को जानने और अपनी जिज्ञासा को निरंतर जीवित रखने की अपील की। उन्होंने लिखा कि एक पुस्तक किसी युवा के जीवन में नया विचार जगा सकती है और एक नया विचार पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है। ध्यान रहे 28 सितंबर को शहीद—ए—आजम भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है। देश की आजादी के लिए उनके संघर्ष, साहस और बलिदान को आज भी याद किया जाता है। भगत सिंह ने कम उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और अपने क्रांतिकारी विचारों से देश के युवाओं में नई चेतना जगाई।

उनका जीवन देशभक्ति, साहस और मातृभूमि के लिए समर्पण की मिसाल माना जाता है। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि गहरे विचार रखने वाले युवा भी थे। उनके लेखों और विचारों में आजादी के साथ—साथ सामाजिक समानता, शोषण से मुक्ति और बेहतर समाज की कल्पना दिखाई देती है। यही वजह है कि उनके विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। 28 सितंबर के इस खास अवसर पर उनके जीवन और योगदान को याद करने के साथ उनके विचारों और देशभक्ति से जुड़े प्रसिद्ध नारों को भी याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर, 1907 को बंगा, पंजाब (अब पाकिस्तान में) में हुआ था। वे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय एक सिख परिवार से थे। उनके पिता किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह क्रांतिकारी थे, उनके चाचा को मांडले निर्वासित कर दिया गया था और बाद में वे सैन फ्रांसिस्को स्थित गार्ड पार्टी से जुड़े। जब भगत सिंह 12 वर्ष के थे तब उन्होंने जलियाँवाला बाग में हुए नरसंहार को देखा, जिससे उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल हुई और उन्हें

जात है उससे वह पितृप्राण स्वयं आप्यापित होता है पुत्र या उसके नाम से उनका परिवार जो यव (जौ) तथा चावल का पिन्ड देता है, उसमें से अंश लेकर वह अम्भप्राण का ऋण चुका देता है। ठीक अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से वह चक्र उर्ध्वमुख्य होने लगता है। 1५ दिन तक अपना—अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितर ब्रह्मंडीय ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं।

पितृपक्ष में हिन्दू लोग मन, कर्म, वाणी से संयम का जीवन जीते हैं, पितरों को स्मरण करके जल चढ़ाते हैं। निर्धनों एवं ब्राह्मणों को दान देते हैं। पितृपक्ष में प्रत्येक परिवार में मृत माता—पिता का श्राद्ध किया जाता है परन्तु गया श्राद्ध का विशेष महत्व है वैसे भी इसका शास्त्रीय समय निश्चित है परन्तु ‘गया सर्वकालेषु पिंड दधाद्विपक्षणम्’ कहकर सदैव पिंडदान करने की अनुमति दे दी गयी है। पुराणों के व्याख्यान में वैसे तो श्राद्ध कर्म या तर्पण करने के भारत में कई स्थान हैं। लेकिन बिहार में पवित्र फल्गु नदी के तट पर बसे प्राचीन गया शहर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पितृपक्ष और पिंडदान को लेकर अलग पहचान है। पुराणों के अनुसार पितरों के खास आश्विन मास के,ष्णपक्ष या पितृष्ण ‘मेक्षायाम गयाजी’ आकर पिंडदान एवं तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता पिता व सात

माता—पिता (पितरों) की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसीलिये हिन्दू धर्मशास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्योपरान्त लोग भूल न जाएं। इसीलिए श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। पुराणों में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति का बड़ा सुन्दर वैज्ञानिक विवेचन मिलता है। मृत्यु के बाद दशगात्र और षोडशी सपिन्धन तक मृत व्यक्तिकी प्रेत संज्ञा रहती है। पुराणों के अनुसार वह सूक्ष्म शरीर जो आत्मा भौतिक शरीर छोड़ने पर धारण करती है। प्रेत होती है। प्रिय की अतिरेक अवस्था प्रेत है क्योंकि आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है, तब भी उसके अन्दर मोह, माया, भूख और प्यास का अतिरेक होता है। सपिन्धन के बाद वह प्रेत, पितरों में सम्मिलित हो जाता है। पितृपक्ष में तो तर्पण किया

बीच बेहतर तालमेल का परिणाम बताया। उनके अनुसार, आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्यवाई के लिए केंद्र और राज्यों की एजेंसियों के बीच समन्वय बेहद जरूरी है।शहजाद भट्टी को पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताया जाता है। भारतीय गृह मंत्रालय के अनुसार, उसके नेटवर्क पर सीमा पार से हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का आरोप है। सरकार का दावा है कि यह नेटवर्क युवाओं और छोटे—मोटे अपराधियों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए उसाने का भी काम करता है। इसी आधार पर गृह मंत्रालय ने सितंबर 2०2६ में इस नेटवर्क को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया था। सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस नेटवर्क का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित नहीं था। अलग—अलग राज्यों में इसके मॉड्यूल सक्रिय थे जिनके जरिए कथित तौर पर अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। 15 राज्यों में 350 लोगों की गिरफ्तारी और 40 से अधिक मॉड्यूल का भंडाफोड़ इस बात की ओर संकेत करता

है कि जांच एजेंसियां इस नेटवर्क को एक संगठित ढांचे के रूप में देख रही हैं।अमित शाह ने सम्मेलन में कहा कि आतंकवाद से मुकाबला केवल किसी एक एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें केंद्रीय सुस्खा एजेंसियों, राज्य पुलिस, खुफिया विभाग और अन्य संस्थानों की सामूहिक भूमिका होती है। सम्मेलन में आतंकवाद से निपटने के लिए तैयार की गई प्रहार रणनीति पर भी चर्चा हुई। सरकार के अनुसार, इस रणनीति के सात प्रमुख स्तंभ हैं— रोकथाम, प्रतिक्रिया, आंतरिक क्षमताओं का एकत्रीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद की परिस्थितियों को कमजोर करना, अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय और पुनर्प्राप्ति एवं लचीलापन। इन सात स्तंभों के माध्यम से आतंकवाद से निपटने की एक व्यापक व्यवस्था विकसित करने की बात कही गई है। अमित शाह ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि ‘प्रहार’ रणनीति को केवल दिल्ली या राज्यों के पुलिस मुख्यालयों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसे थाने के स्तर तक लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से जुड़े किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पुलिस व्यवस्था को

विचार 4जौनपुर,गुरुवार ०1 अक्टूबर, 2026

भगत सिंह का संदेश देती योगी की पाती

भारत की स्वतंत्रता के लिये लड़ने की प्रेरणा मिली। बाद में उन्होंने लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जहाँ उन्हें स्वदेशी और क्रांतिकारी विचारों से परिचित कराया गया। भगत सिंह वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने, बाद में वर्ष 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। वर्ष 1926 में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिये युवाओं को संगठित करने हेतु नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इसके बाद वर्ष 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक (राजनीतिक गतिविधियों को दबाने और व्यक्तियों को निर्वासित करने) और व्यापार विवाद विधेयक (श्रमिकों के हड़ताल करने के अधिाकार पर अंकुश लगाने) का विरोध ा करने के लिये केंद्रीय विधानसभा में कम तीव्रता वाले बम फेंके। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस (1928) में दोषी ठहराया गया था, जिसमें लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या शामिल थी, जिसे लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिये अंजाम दिया

गया था। तीनों को 23 मार्च, 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फाँसी दे दी गई। भगत सिंह एक कट्टर नास्तिक और समाजवादी थे, जो मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की और बाकुनिन जैसे विचारकों से प्रभावित थे। उनकी रचनाएँ, जिनमें में नास्तिक क्यों हैं भी शामिल है। तर्कवाद, समानता और सामाजिक न्याय में उनके विश्वास को दर्शाती हैं।

भगत सिंह ने अमृतसर के उर्दू और पंजाबी समाचार पत्रों के लिये लेखन किया, साथ ही उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी की पत्रिका ‘कीर्ति’ में भी लिखा और कुछ समय हेतु दिल्ली के ‘वीर अर्जुन’ समाचार पत्र में भी कार्य किया। वे प्रायः बलवंत, रंजीत और विद्रोही जैसे उपनामों का प्रयोग करते थे।

भगत सिंह, जिन्हें ‘शहीद—ए—आजम’ की उपाधि दी गई, ने ‘इंकलाब जिंदाबाद’ का नारा दिया, जो भारत की आजादी की लड़ाई का एक सशक्त घोषवाक्य बन गया। हमारे देश में प्रतिवर्ष 23 मार्च को भारत स्वतंत्रता सेनानियों— भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को सम्मान देने के लिये शहीद दिवस मनाया जाता है।



पीढ़ियों का उद्धार होता है। पितृ की श्रेणी में मृत पूर्वजों, माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी सहित सभी पूर्वज शामिल होते हैं व्यापक दृष्टि से मृत गुरु और आचार्य भी पितृ की श्रेणी में आते हैं। कहा जाता है कि गया में पहले विभिन्न नामों के 360 वेदियां थीं, जहां पिंडदान किया जाता था इनमें अब 48 ही बची हैं। यहां की नंदी के किनारे अथवयद पर पिंडदान करना जरूरी माना जाता है। इसके अतिरिक्त बैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुण्ड, नागकुण्ड, पाण्डुशिला, रामशिला, मंगलागौरी, कागबलि आदि भी पिण्डदान के लिए प्रमुख है। यही कारण है कि देश में श्राद्ध के लिए ५५ स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें गया का स्थान स्वीपर है।गया का पुराणों में उल्लेख पितृश्राद्ध एवं पिण्डदान का कई कारणों से महत्व दर्शाता है। बताया जाता है कि गयासुर नामक असुर ने कठिन

तपस्या कर ब्रह्म जी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाये और लोग उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जायें। इस वरदान के चलते लोग भयमुक्त होकर पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन से फिर पाप मुक्त हो जाते थे। इससे बचने के लिए देवताओं ने यज्ञ के लिए गयासुर से पवित्र स्थान की मांग की। गयासुर ने अपना शरीर देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया। जब गयासुर लेटा तो उस का शरीर पांच कोस में फैल गया। यही पांच कोस जगह आगे चलकर गया बना। यह भी उल्लेख है कि देहदान के बाद गयासुर के मन से लोगों को पाप मुक्त करने की इच्छा नहीं गई और फिर से देवताओं से वरदान मांगा कि यह स्थान लोगों को तारने वाला बना रहे। तब से ही यह स्थान मृतकों के लिये श्राद्धकर्म मुक्ति का स्थान बन गया।

आतंकवाद पर अमित शाह का प्रहार

काश्मीर की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने मेंमदद मिलने की उमीद है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह सचिव गोबिंद मोहन, विदेश सचिव किरम मिसर, खुफिया ब्यूरो के निदेशक मोहन दीक्षित, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस सांठनों के प्रमुखों सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 1५ राज्यों के पुलिस महानिदेशक और सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के आतंकवाद निरोधक दस्तों के प्रमुखोंने भी इसमें हिस्सा लिया। अन्य राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। इस बैठक का एक महत्वपूर्ण पक्ष केंद्र और राज्यों के बीच सुस्खा संबंधी जिम्मेदारियों का बंटवारा और समन्वय भी रहा। भारत में कानून—व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य का विषय है, जबकि आतंकवाद, सीमा पार गतिविधियों और राष्ट्रीय सुस्खा से जुड़े मामलों में केंद्रीय एजेंसियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में किसी बड़े नेटवर्क के खिलाफ कांश्याई के लिए दोनों स्तरों पर सूचनाओं का आदान—प्रदान और संयुक्त जांच आवश्यक हो जाती है।शहजाद भट्टी

नगर प्रवेश स्थल का नाम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तिराहा करने की मांग



फतेहपुर। नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 02 आवास विकास कालोनी के सभासद दीपक कुमार मौर्य ने नऊवाबाग हाईवे स्थित शहर के प्रमुख प्रवेश स्थल को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तिराहा के रूप में विकसित एवं नामित किए जाने की मांग की है। उन्होंने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी को पत्र सौंपकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया।सभासद ने पत्र में कहा कि नऊवाबाग हाईवे शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों में से एक है। इस प्रवेश स्थल को सुव्यवस्थित, आकर्षक एवं ऐतिहासिक पहचान देने के उद्देश्य से यहां सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तिराहा विकसित एवं नामित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इससे ऐतिहासिक विरासत के प्रति जन-जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ शहर के प्रमुख प्रवेश द्वार को भी विशिष्ट पहचान मिल सकती है। सभासद ने नगर पालिका से स्थल का स्थानीय एवं तकनीकी सर्वेक्षण, सड़क सुखा, भूमि की उपलब्धता तथा संबंधित विभागों

की अनुमति को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार कराने की मांग की है। प्रस्ताव में उपयुक्त स्थल का चयन, आकर्षक नामपट्ट/साइन बोर्ड लगाने, स्थल के सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था और आवश्यकता के अनुसार संबंधित ऐतिहासिक प्रतीकात्मक संरचना विकसित करने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है तो संबंधित विभागों से आवश्यक एनओसी एवं अनुमति प्राप्त की जाए। यातायात पुलिस एवं संबंधित अभियंत्रण विभाग से तकनीकी परामर्श लेकर ऐसा डिजाइन तैयार करने का सुझाव दिया गया है, जिससे यातायात प्रभावित न हो। सभासद ने प्रस्ताव को नगर पालिका परिषद के सक्षम बोर्ड/समिति के समक्ष रखकर नियमानुसार स्वीति एवं बजट की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। साथ ही परियोजना शुरू करने से पूर्व भूमि स्वामित्व, राइट ऑफ वे, यातायात सुखा एवं निर्माण संबंधी तकनीकी आवश्यकताओं की जांच कराने का भी अनुरोध किया है।

मलवां सिलेंडर हादसे में कांग्रेस ने मांगी पांच लाख की सहायता



फतेहपुर। मलवां कस्बे में सिलेंडर विस्फोट से दो मंजिला मकान जमींदोज होने व चार लोगों की मौत के बाद बुवार को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने हादसे की पूरी जानकारी जुटाकर मामले से प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराने की बात कही। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी ने मृतकों के परिजनों को दी जा रही सहायता राशि को नाकाफी बताते हुए प्रत्येक मृतक के परिवार को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की।जिलाध् यक्ष ने कहा कि सिलेंडर विस्फोट में पूरा मकान तबाह हो गया, जिससे पीड़ित परिवार के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली दो लाख रुपये

की सहायता राशि पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि संकट की घड़ी में परिवार को कुछ राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि विस्फोट से आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में घटना स्थल के आसपास क्षतिग्रस्त हुए मकानों का सर्वे कराकर प्रभावित परिवारों को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे उनके नुकसान की कुछ भरपाई हो सके। प्रतिनिधिमंडल में जिला उपाध्यक्ष कलीम उल्लाह सिद्दीकी, मुन्ना कोरी, प्रेम शंकर बाजपेयी, गजेंद्र द्विवेदी, मो. इदरीस व उमेश कुमार शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांडस बंधाया और हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।

नीलम करवरिया कप का बिगुल फूँका

प्रयागराज। जिले के प्रतिष्ठित नीलम करवरिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण का रोमांच शुरू होने को है। आयोजकों ने बहुमतीक्षित टूर्नामेंट के गुप्त का आधिकारिक ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ही 12 वि्ठानसभा टीमों के बीच खिताबी मि्रंट की रूपरेखा तय हो गई है। आयोजन सचिव सख्कम करवरिया ने बताया कि 10 से 17 अक्टूबर तक कैप्टल मैदान की 22 गज की पट्टी पर चौके-छक्कों की जंग देखने को मिलेगी। टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें ताल ठोकेंगी, जिन्हें तीन-तीन के संतुलन के साथ 4 अलग-अलग ग्रुपों में बांटा गया है।

ग्रुप का समीकरण

ग्रुप ए (डिफेंडिंग चैंपियन का इम्तिहान)रु गत विजेता शहर उत्तरी विधानसभा की टीम अपने खिताब का बचाव करने उत्तरेगी। इस ग्रुप में उसे चुनौती देने के लिए फूलपुर और कोरांव की टीमें कम्पर कस चुकी हैं।ग्रुप बी (स्थानीय प्रतिद्वंद्वितो)रु इस ग्रुप में रोमांच चरम पर रहने की उम्मीद है, जहां शहर पश्चिमी विधानसभा, शहर दक्षिणी और पिछली उपविजेता सोरांव विधानसभा की टीमें आमने-सामने होंगी।ग्रुप सी (कड़ मुकाबला)रु प्रतापपुर, मेजा और कच्छला विधानसभा की टीमें सेमीफाइनल का टिकट कटाने के लिए एक-दूसरे से वे-दो हाथ करेंगी।ग्रुप डी (अंतिम घमासान)रु चौथे और अंतिम ग्रुप में फाफामऊ, बारा और हंडिया विधानसभा की टीमों के बीच सेमीफाइनल की रस देखने को मिलेगी।10 अक्टूबर से शुरू हो रहे इस 8 दिवसीय क्रिकेट महाकुंभ के लिए टीमें मैदान पर पसीना बहाने में जुट गई हैं। पिच और परिस्थितियों को देखते हुए मुकाबला बेहद कांटे का रहने की उम्मीद है।

पहले दर्ज कराई एफआईआर फिर बोले चालान की थी रकम

प्रयागराज। संगम क्षेत्र के पेरंड मैदान में श्रद्धालुओं की बस रोककर कथित रूप से वसूली करने का वीडियो वायरल होने के बाद दारागंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई। यह एफआईआर आरटीओ प्रवर्तन सचेंद्र प्रकाश सिंह की ओर से दर्ज कराई गई। एफआईआर कराने वाले अफसर ने ही यू टर्न लेते हुए बुवार को यह भी कहा कि सरकारी गाड़ी में बैठा व्यक्ति यात्री कर अधिकारी का निजी ज़इवर है। यह भी बताया कि वह जो पैसे गिनता नजर आ रहा है, वह चालान की राशि थी। उनके इस कथान को लेकर अब तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं।

ज्ञात हो कि यह वीडियो मंगलवार को सामने आया था। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार लिखी एक बोलेरो में पीछे की सीट पर बैठा व्यक्ति कैश गिनता नजर आता है। जबकि दरवाजे के विंडो पर एक व्यक्ति खड़ा नजर आता है। नोट गिनने के बाद गाड़ी में बैठा व्यक्ति अधिकारी रणविजय सिंह चौहान को इठीक हैर कहता है और इसके बाद

कार के दरवाजे की विंडो से भीतर झांक रहा व्यक्ति चला जाता है। वीडियो में जो गाड़ी नजर आती है, उस पर लाल-नीली बत्ती के साथ हूटर भी लगा हुआ था। बाद में यह बात सामने आई कि यह वाहन आरटीओ के यात्री कर अधिकारी रणविजय सिंह चौहान को आवंटित है।सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के साथ यह भी आरोप लगाया गया कि स्लीपर बस में सवार होकर एमपी के सतना से श्रद्धालुओं का जल्था फिडान के लिए संगम आया था। वहां से लौटते वक्त ही उन्हें रास्ते में रोककर वसूली की गई। इसमें वायरल वीडियो का हवाला देते हुए बताया गया कि पुष्पेंद्र सिंह नाम का निजी व्यक्ति यात्रीकरमालकर गिनने के बाद गाड़ी में बैठा व्यक्ति आवंटित सरकारी वाहन में बैठकर

नकदी गिन रहा था। तहरीर में वीडियो को सोशल मीडिया पर रिश्त की रकम के रूप में प्रसारित किए जाने का उल्लेख किया गया। रात 11रु30 बजे के करीब इस मामले में आरोपी पुष्पेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।इस बाबत जब एआरटीओ प्रवर्तन सचेंद्र प्रकाश सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यात्री कर अधिाकारी के वाहन में दिखाई दे रहा पुष्पेंद्र सिंह उनका निजी ड्राइवर है। प्रारंभिक जांच में यह बात पता चली है कि वह जो पैसे गिन रहा है, वह चालान की राशि है।

प्रयागराज। आर.पी. रस्तोगी इंटरमीडिएट कॉलेज, मलाक हरहर प्रयागराज में बुधवार को विधायक निधि रुपए 5 लाख से निर्मित 225 फीट लंबी बाउंड्री वॉल का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक गुरु प्रसाद मौर्य ने किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की वास्तविक जिम्मेदारी जनता की आवश्यकताओं को समझकर उनके समाधान की दिशा में कार्य करना है। क्षेत्र में जहां जिस सुविधा की आवश्यकता

बारिश से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग - अपना दल एस ने सीएम को भेजा पत्र, फसल नुकसान के सर्वे के साथ आपदा राहत की मांग



लिखे जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही लगातार बारिश से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का सर्वे कराकर प्रभावित परिवारों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग भी की गई। पत्र में किसानों और बारिश प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। इस मौके पर पदम सिंह पटेल, योगेंद्र सिंह राजा, दीपू पटेल, पपू वर्मा, कान्ती कुषवाह, अरुण पटेल, गुलाब सिंह, दिलदार अली, डा. शिवप्रकाश रावत, सुनील पटेल, सोनू पासवान, अतीष कुमार पटेल, दीपांशु पटेल आदि मौजूद रहे।

48 घंटे में खुलासे का आश्वासन पर धरना खत्म

सुल्तानपुर। शिक्षक दंपति मुकेश सिंह और उनकी पत्नी विनीता सिंह की हत्या की घटना से जनपद

मार्ग पर धोपाप पुल से पहले शव रखकर धरना—प्रदर्शन शुरू कर दिया। शिक्षक संगठनों ने हत्याकांड



में आक्रोश का माहौल है। शिक्षक भयाक्रांत हैं। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने कादीपुर—धोपाप

का शीघ्र खुलासा करने और आरोपियों की गिरतारी की मांग उठाई। पुलिस अधिाक्षक विनीत जायसवाल ने प्रदेश अध्यक्ष को फोन किया और एसपी को भेजा। अपर पुलिस अधीक्षक बृजराज सिंह पुलिस के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ और धोपाप घाट पर शिक्षक दंपति का अंतिम संस्कार किया गया। धोपाप घाट पर क्षेत्राधिकारी कादीपुर विनय गौतम भी पहुंचे और परिजनों तथा शिक्षक नेताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन जल्द कार्रवाई की

मांग पर अड़े रहे। बाद में अपर पुलिस अधीक्षक बृज राज सिंह मौके पर पहुंचे। शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों और परिजनों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने 48 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा करने तथा आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए।इस दौरान उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध् यक्ष विनय तिवारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह भी धोपाप पहुंचे। दोनों पदाधिकारियों ने जनपद के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल से वार्ता कर पीड़ित परिवार की मांगों को पूरा कराने तथा मामले में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष की प्रयासों के बाद परिवार की मांगों पर कार्रवाई के संबंध में लिखित आश्वासन दिया गया, जिसके उपरांत पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए घाट पर ले

जाया गया।धोपाप घाट पर शिक्षक दंपति के अंतिम संस्कार के दौरान माहौल अत्यंत गमगीन रहा। बेटे ने अपने माता—पिता को मुखाग्नि दी। इस हृदयविदारक श् य ने उपस्थित लोगों को भावुक कर दिया। शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों, शिक्षकों और शुभचिंतकों ने दिवंगत दंपति को श्रद्धासुमन अर्पित कर परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उध्ार, मृतक मुकेश सिंह के भाई यक्ष विनय तिवारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह भी धोपाप पहुंचे। दोनों पदाधिकारियों ने पुलिस जांच में जुटी है। शिक्षक संगठनों ने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए हत्याकांड के शीघ्र खुलासे और दोषियों की गिरतारी की मांग की है। अब पूरे जनपद की निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं। शिक्षक समुदाय और पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि पुलिस निध्ारित समय में मामले का खुलासा कर दोषियों को कानून

के कठघरे तक पहुंचाएगी। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी, राष्ट्रीय सचिव अर्जुन सिंह, गोंडा के जिला संयुक्त मंत्री बलवंत सिंह, पदाधिकारी महेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष दिनेश उपाध्याय, जिला मंत्री राम आशीष मौर्य, जिला उपाध्यक्ष एवं प्रदेश मंत्री रमेश तिवारी जनपद के सभी शिक्षक संगठनों के जिला अध्यक्षों के साथ जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, रणवीर सिंह, वैभव भटनगर, दीपेन्द्र सिंह, कोषाध्यक्ष विनय प्रजापति, विपिन यादव, फिरोज अहमद अरुण सिंह, राहुल मिश्रा, डॉ. चन्द्रपाल राजभर, राजीव यादव, रामचंद्र राजभर, सुरेश सिंह, के.सी. मिश्रा, पंकज मिश्र सहित विभिन्न शिक्षक संगठनों के जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, ब्लॉक अध् यक्ष, मंत्री एवं हजारों की संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।

1941 के पट्टे पर फिर उठे सवाल, 2024 में शिकायत खारिज फिर भी जीर्णोद्धार पर रोक

सुल्तानपुर। सिविल लाइन स्थित श्री तुलसी सत्संग भवन समिति ने जिला प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। समिति के कोषाध्यक्ष आशीष पांडेय ने 30 सितंबर को संपादक के नाम जारी पत्र में दावा किया कि भवन और भूमि से जुड़े विवाद की प्रशासनिक जांच पहले ही हो चुकी है और 27 सितंबर 2024 को तत्कालीन जिलाधिकारी ने लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए पट्टे की अवधि 17 नवंबर 2026 तक विधिमान्य मानी थी। इसके

बावजूद भवन के जीर्णोद्धार का काम प्रशासनिक दबाव में रोक दिए जाने का आरोप लगाया गया है। समिति के मुताबिक गाटा संख्या 368 की भूमि का 90 वर्ष का पट्टा 18 नवंबर 1941 को उसके पक्ष में किया गया था। राजकीय अभिलेखागार के ग्राम खतौनी सदर सुल्तानपुर में 1397 फसली में भी गाटा संख्या 368ध्. 1041 हेक्टेयर का उल्लेख होने का दावा पत्र में किया गया है। समिति ने कहा कि भवन नगरपालिका परिषद सुल्तानपुर के असेसमेंट रजिस्टर में

सिविल लाइन नंबर 1 के मकान संख्या 1044 पर पंजीत है। समिति के अनुसार वह लगातार भवन का जल एवं गृहकर नियमानुसार जमा करती रही है। पत्र में यह भी कहा गया है कि भवन में बेसिक शिक्षा विभाग का लेखा—कार्यालय लंबे समय तक किरायेदार के रूप में संचालित रहा। किराये की रकम समिति के बैंक खाते में जमा होती थी। समिति का दावा है कि इसी धनराशि से कुंभ और माघ मेले में शिविर लगाकर कल्पवासियों की निरुशुक सेवा

की जाती रही है। समिति ने अदालत में लंबित मामले को लेकर भी अपना पक्ष रखा है। पत्र के अनुसार सिविल जज (ग्रंथम) के न्यायालय में वाद संख्या 298/21.कमला तिवारी बनाम तुलसी सत्संग भवन में दिया गया स्थगनादेश 11 अगस्त 2023 को निरस्त किया जा चुका है। वहीं हाईकोर्ट में दाखिल 10186—2021 के संबंध में समिति ने कहा है कि 16 जून 2021 के आदेश में प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का स्थगनादेश पारित नहीं किया गया। समिति ने

आरोप लगाया कि कुछ लोगों की शिकायतों के आधार पर प्रशासन को बार—बार ऐसी जानकारी दी जा रही है, जिससे भवन का जीर्णोद्धार प्रभावित हो रहा है। समिति का कहना है कि जर्जर भवन की महम्मत और जीर्णोद्धार कराया जा रहा था, लेकिन प्रशासनिक दबाव के कारण काम पूरी तरह रुक गया है। समिति ने प्रशासन से पूरे मामले में राजस्व अभिलेख, पूर्व जांच रिपोर्ट और न्यायालय के आदेशों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

रेलवे अस्पताल के सुरक्षाकर्मियों का धरना पर तीसरे दिन भी जारी

6 महीने का वेतन बकाया, फील्ड आफिसर ने दी निकालने की धमकी

प्रयागराज। सिविल लाइंस स्थित रेलवे अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों का वेतन भुगतान को लेकर तीन दिनों से धरना जारी है। छह महीने का वेतन बकाया था, जिसमें दो महीने की सैलरी अब खातों में भेजी गई है। कर्मचारियों का कहना है कि चार महीने का भुगतान अभी बाकी है। पूरा वेतन नहीं मिलने तक उन्होंने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया है।सुरक्षा कर्मियों ने घर का किराया, बच्चों की फीस और परिवार के दूसरे खर्चों का हवाला देते हुए जल्द पूरा भुगतान करने की मांग की है। वहीं, फील्ड ऑफिसर पर धरना खत्म करने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है।।सुरक्षा कर्मियों के अनुसार उन्हें छह महीने से वेतन नहीं मिला था। धरना शुरू होने के बाद ठेकेदार की ओर से दो महीने की सैलरी खातों में भेजी गई, लेकिन चार महीने का बकाया अभी बाकी है। कर्मचारियों ने बताया कि वेतन नहीं मिलने से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। कर्मचारियों के मुताबिक, धरना खत्म नहीं करने पर पुलिस बुलाकर लात मारकर बाहर निकलवाने और उनकी जगह दूसरे लोगों को काम पर रखने की बात कही गई। कर्मचारियों का कहना है कि तीन दिन से धरना चल रहा है, लेकिन रेलवे का कोई अधिकारी उनकी समस्या सुनने मौके पर नहीं पहुंचा। उन्होंने बताया कि धरने के दौरान खाने—पीने का इंतजाम भी नहीं है और आसपास के लोग जो मदद करते हैं, उसी से काम चल रहा है।सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि चार महीने का बकाया मिलने के बाद ही वे धरना खत्म करेंगे। उन्होंने वेतन भुगतान के साथ पीएफ और ईएसआई की समस्या दूर करने की भी मांग की है।

सिविल लाइंस में विकसित होंगे कई स्थानों पर पार्किंग स्थल

प्रयागराज। मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. की अध्यक्षता एवं उपाध् यक्ष विकास प्राधिकरण ऋषिराज, नगर आयुक्त साई तेजा, डीसीपी मनोष शाण्डिल्य सहित संबंधित अधिाकारियों तथा विभिन्न व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सिविल लाइन्स क्षेत्र में एमजी रोड एवं सरदार पटेल मार्ग को सुव्यवस्थित एवं सुंदर बनाने, यातायात को सुगम करने तथा अतिक्रमण की समस्या के समाधान के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में व्यापार मंडल प्रतिनिधि र्यों ने दोनों मार्गों पर यातायात जाम एवं अतिक्रमण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनकी मंडलायुक्त ने

बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।एमजी रोड पर हनुमान मंदिर चौराहे से पत्थर गिरजाघर तक सड़क एवं सर्विस लेन के बीच का विभाजन हटाकर उचित ढलान तैयार करने तथा सड़क किनारे पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। थॉर्नहिल रोड की तर्ज पर ऐसी पार्किंग व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिसमें वाहन सुगमता से प्रवेश कर सड़क किनारे व्यवस्थित रूप से पार्क किए जा सकें। इससे सड़क की उपयोगी चौड़ाई बढ़ने के साथ ही यातायात व्यवस्था भी अधिाक सुगम होगी।इसी प्रकार सरदार पटेल मार्ग पर खरबंदा मोर्टर्स के

सामने से विवेकानंद चौराहे तक दोनों ओर बनी फुटपाथ की रेलिंग हटाकर उसके ढलान को सड़क के अनुरूप व्यवस्थित करने तथा पार्किंग के लिए अतिरिक्त स्थान विकसित करने के निर्देश दिए गए। मंडलायुक्त ने डीसीपी को तीन दिवस के भीतर सभी अनावश्यक अवरोध हटाने के निर्देश दिए। नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण की टीम के साथ समन्वय स्थापित कर मलबा एवं अन्य सामग्री हटाने, सड़क की



साफ—सफाई कराने तथा अनधिकृत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि नागरिकों का आवागमन सुगम एवं सुरक्षित हो सके।

विधायक ने किया 225 फीट लंबी बाउंड्री वाल का लोकार्पण

हो, वहां विकास कार्य कराना जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। बाउंड्री वॉल के लिए अनुदान इस दिशा में मेरे द्वारा एक छोट सा प्रयास है। जो इस विद्यालय की आवश्यकता के अनुकूल है।कार्यक्रम में क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती आरती मौर्य ने विद्यालय में हो रहे विकास कार्यों की सरहना की। प्रधानाचार्य ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। इसी अवसर पर सम्मग शिक्षा के अंतर्गत अनुदानित व्यावसायिक प्रयोगशाला का उद्घाटन की विधायक गुरु प्रसाद मौर्य ने किया। प्रधानाचार्य

ने बताया कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप यह प्रयोगशाला विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध कराने मेंमहत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा उन्हें कौशल आधारित शिक्षा से जोड़ने में सहायक होगी।कार्यक्रम में महिंद्रा फाउंडेशन के

सहयोग से संचालित 'नन्ही कली परियोजना' के अंतर्गत विद्यालय की 172 छात्राओं को जूतों का वितरण किाायक द्वारा किया गया। समारोह में विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं, कर्मचारी, विद्यार्थी एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

हनुमान अंश बाक्स ऑफिस: वर्ल्डवाइड 400 करोड़ का आंकड़ा पार, शाहरुख, आमिर और ऋतिक की फिल्म को चलाई धूल



हनुमान अंश इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपना नाम दर्ज करवा चुकी है. फिल्म अपनी रिलीज के शानदार 52 दिन पूरे कर चुकी है और अभी भी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ रुपये की फिगर में कमाई कर रही है. 52वें दिन फिल्म की कमाई में लगभग 50 फीसदी का उछाल आया और फिल्म ने भारत में 300 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया.महज 2 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश ने कमाई से इतिहास रच डाला है. यह फिल्म टॉप 50 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो गई. फिल्म अपने शानदार सात हफ्ते पूरे कर चुकी है. वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर कई बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है. चलिए एक नजर डालते हैं हनुमान अंश की अब तक की कमाई पर.हनुमान अंश ने शुरुआत में कोई खास कमाल नहीं दिखाया. महज 10 लाख रुपये से ओपनिंग की और आज 52वें दिन फिल्म ने लगभग 10 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. फिल्म की शुरुआत धीमी रही और पहले दो हफ्तों में तो इसे लगभग फ्लॉप मान लिया गया था. फिल्म पहले दो हफ्तों में मुश्किल से 1.50 करोड़ रुपये ही कमा पाई. हालांकि, इसके बाद दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली और टिकटों की बिक्री में तेजी से उछाल आया. चौथे हफ्ते से हनुमान अंश हर हफ्ते भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपये से अधिक का प्रॉफिट कमा रही है.

डायरेक्टर इशिका के काम की दीवानी हुई अदा खान, बोलीं- मैं तो बस देखती ही रह गई

अभिनेत्री अदा खान साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज द लिपट में नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने सीरीज को लेकर अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि शूट के दौरान सभी एक्टर्स के बीच में बॉन्ड काफी अच्छा बन गया था। अभिनेत्री ने कहा, हर दिन हमारा एक नया अनुभव होता था। एक ताजगी का एहसास था और मैं खुद भी कुछ नया महसूस कर रही थी। काफी समय से मुझे ऐसा कुछ करने का मौका नहीं मिला था। इस शो ने मुझे अलग ही खुशी दी और मुझे इस पर काम करके बहुत मजा आया। अदा खान ने सीरीज में अभिनेता प्रतीक सहजपाल के साथ काम करने को लेकर भी बात की।

उन्होंने माना कि वह खुद इंट्रोवर्ट हैं और जल्दी दोस्ती नहीं कर पातीं लेकिन प्रतीक ने उन्हें टीम के साथ घुलने-मिलने में मदद की। उन्होंने कहा, प्रतीक ऐसा इंसान है जो खुद ही माहौल को हल्का कर देता है। वह बहुत ही चिल्ड-आउट इंसान है। आप उसके साथ बातें करते रह सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। मुझे लगता है कि



वह उन गिने-चुने लोगों में से एक है जिसके साथ मुझे खुलने में ज्यादा समय नहीं लगा।

अभिनेत्री ने बताया कि वह शूट के दौरान निर्देशक इशिका के काम से भी काफी प्रभावित रहीं थीं। उन्होंने कहा, मैं कह सकती हूँ कि मैं उनके काम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी, या कहूँ तो मंत्रमुग्ध थी। पूरे शूट के दौरान मैं बस उनके काम को देखती रह गई।इसके साथ ही शो की कहानी के बारे में बात करते हुए अदा ने कहा, हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। मुझे लगता है कि हर किरदार के पीछे एक साइकोलॉजिकल पहलू होता है। मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहती लेकिन हर किरदार में कई परतें हैं और उन्हें एक्सप्लोर करना काफी दिलचस्प रहा।अदा खान ने बताया कि लिपट जैसी छोटी जगह में सुबह से लेकर पैकअप तक लंबे समय तक साथ रहने से एक्टर्स को बातचीत करने, रिलैक्स करने और बॉन्डिंग करने का खूब मौका मिला, भले ही उनके सीन खत्म हो चुके हों। उन्होंने कहा कि इससे कास्ट के बीच एक बिल्कुल अलग तरह की बॉन्डिंग बनी।



ऋ चा चड्ढा लेकर आई नया ट्रैवल शो मुसाफिरी, दिखेगा मुंबई का अनदेखा इतिहास

अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की नॉन-फिक्शन ट्रैवल सीरीज मुसाफिरी का पहला एपिसोड रिलीज हो रहा है। इस सीरीज में मुंबई शहर के इतिहास, वहां के समुदायों, छिपी हुई कहानियों और कम चर्चित जगहों को दिखाया जाएगा। पहले एपिसोड में मुंबई के इतिहास, कल्चर और कुछ सबसे हैरान करने वाले राज दिखाए गए हैं। इस एपिसोड में किम कार्दशियन और साउथ मुंबई के सबसे मशहूर इलाकों में से एक काला घोड़ा के बीच एक अनोखा कनेक्शन भी बताया गया है। ऋचा ने मुंबई को भी एक्सप्लोर किया है और शहर के देवी-देवताओं से जुड़े दिलचस्प किस्से बताए हैं, जिनमें मां महालक्ष्मी भी शामिल हैं, जिन्हें मुंबई की माता देवी माना जाता है।अभिनेत्री का मानना है कि मुंबई शहर ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है, जिनके बीच लोग बड़े होते हैं लेकिन कभी रुकककर उन्हें जानने की कोशिश नहीं करते। अभिनेत्री ने कहा, मुंबई में इतनी सारी कहानियां हैं, जिनके बीच हम बड़े हुए हैं, लेकिन लोगों के साथ मैं इन्हें शेयर करना चाहती थीं।एपिसोड में दर्शकों को मुंबई के सबसे पुराने आर्मेनियाई चर्चों में से एक में भी ले जाया जाता है और गेटवे ऑफ इंडिया के इतिहास और इसे क्यों बनाया गया था, इसके बारे में भी बताया गया है। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जो लोग पूरी जिंदगी मुंबई में रहे हैं, वे भी शहर को एक अलग नजर से देखेंगे और उन्हें लगेगा जैसे वे एक नई मुंबई को खोज रहे हैं।

मुसाफिरी का पहला एपिसोड आज शाम उनके यूट्यूब चैनल फुलस्टॉप पर आएगा।

एविंग्स की बात करें तो, वह आखिरी बार संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित हीरामंडीरू द डायमंड बाजार में देखी गई थीं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाहौर के हीरा मंडी के रेड-लाइट एरिया पर बनी यह सीरीज ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत तवायफों के जीवन और राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों के साथ उनके जुड़ाव को दिखाती है।

सीरीज में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख, शर्मिन सहगल और ताहा शाह बटूशा शामिल हैं। सिनेमा में वह आखिरी बार मृगदीप सिंह लांबा द्वारा डायरेक्टेड फुकरे 3 में देखी गई थीं।



द वन का ओपनिंग वीकेड पर गदर, हैवान से पेद्दी तक साल की 26 फिल्मों की लाइफटाइम कमाई को दी मात

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया अभिनीत लोक-कथा आधारित रोमांचक फिल्म इंद वनरू फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट्स सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। अच्छी शुरुआत के बाद फिल्म की कमाई में दूसरे दिन बढोतरी देखने को मिली और रविवार को तीसरे दिन इसके कारोबार में और बड़ा उछाल आया। शुरुआती सप्ताहांत में फिल्म ने कुल 33.25 करोड़ रुपये का शुद्ध कारोबार कर लिया है।

श्पंचायतच के लिए मशहूर निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में बनी यह फिल्म पौराणिक लोककथाओं, काल्पनिक दुनिया, रोमांच, रहस्य और अलौकिक शक्तियों को एक साथ पेश करती है। फिल्म में बिहार की लोककथाओं और सांस्कृतिक परिवेश की झलक के साथ आस्था के महापर्व छठ को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। यही वजह है कि बिहार के साथ दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी फिल्म को लेकर दर्शकों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है।

फिल्म के कारोबार की बात करें तो इंद वनच ने पहले दिन शुक्रवार को 8 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की थी। इसके बाद शनिवार को फिल्म के कारोबार में अच्छी बढ़ोतरी हुई और इसने



1125 करोड़ रुपये कमाए।

वहीं, सैकनलक की शुरुआती रुझान रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने तीसरे दिन यानी रविवार को करीब 14 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसके साथ ही तीन दिनों में फिल्म की कुल शुद्ध कमाई 33.25 करोड़ रुपये हो गई है।इंद वनच ने शुरुआती सप्ताहांत में ही कई फिल्मों के पूरे सिनेमाघर कारोबार को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, 33.25 करोड़ रुपये के तीन दिवसीय कारोबार के साथ फिल्म ने 2026 में प्रदर्शित श्रेष्ठान्य और श्रेष्ठेय के हिंदी संस्करण समेत करीब 26 फिल्मों के जीवनकाल के कारोबार को मात दे दी है।फिल्म की कमाई में लगातार हो रही बढ़ोतरी को इसके प्रति दर्शकों की बढ़ती दिलचस्पी से जोड़कर देखा जा रहा है। शुक्रवार को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया और शनिवार के बाद रविवार को कारोबार मेंआई तेजी ने फिल्म के निर्माताओं के लिए उम्मीदेंबढ़ दी है।इंद वनच की कहानी एक समझदार और शहर मेंपले-बढ़ेयक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है। उसका जीवन उस समय पूरी तरह बदल जाता है जब वह अपने पुरेसी गांव से जुड़े एक प्रतिबिंबित जंगल मेंपहुंछता है। वहां एक प्राचीन दैवीय शक्ति को छेड़ने के बाद उसका सामना ऐसी अलौकिक शक्तियोंसे होता है जिन्हेंसामान्य तर्क से समझ पाना मुश्किल है।इसके बाद वह अपने लोगोंको एक बड़ेखतरे से बचाने की जिम्मेदारी उठाता है। फिल्म में लोकविश्वास, रहस्य, रोमांच और अलौकिक शक्तियों के साथ बिहार की लोकसंस्कृति को भी कहानी का अहम हिस्सा बनाया गया है। छठ पूजा के दृश्यों ने फिल्म को बिहार और पूरेभारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सेभी जोड़दिया है।फिल्म मेंसिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिकाओं में हैं। इनके अलावा सुनील ग्रोवर, अनूप सोनी, श्वेता तिवारी और मनीष पॉल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आए हैं। दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में बनी यह फिल्म लोककथा, कल्पना, साहसिक रोमांच, रहस्य और अलौकिक घटनाओं के मिश्रण के रूप में दर्शकों के सामने पेश की गई है।

भ्रष्टाचार और घोटाले के विरुद्ध 1878 दिनों से सत्याग्रह जारी



जौनपुर | जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण घोटाले, भ्रष्टाचार और पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ चलाया जा रहा सत्याग्रह आन्दोलन 1878वें दिन भी जारी रहा। आन्दोलनकारी यशवन्त कुमार गुप्त के नेतृत्व में 9 अगस्त 2021 से चल रहे इस अनवरत धरने के माध्यम से भूमि अधिग्रहण में हुई अनियमितताओं और जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतों के फर्जी निस्तारण का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। इस अवसर पर यशवन्त कुमार गुप्त ने स्पष्ट किया कि यह आन्दोलन जांच के मुख्य बिंदुओं पर अडिग है और समस्या के समाधान तक जारी रहेगा। सत्याग्रह के दौरान सिरकोनी बाजार (इजरी) में हुई भीषण डकैती के अभियुक्तों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। इस अवसर पर उदय प्रताप सिंह, रामनगीना यादव, अमरेश कुमार पाण्डेय, प्रेम प्रकाश मिश्र, आदित्य नारायण शर्मा, नरेंद्र गिरी, छेदीलाल साहू, बसन्त लाल मौर्य, उपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, विजय प्रताप सिंह, सजन यादव, डा.ज्ञान प्रकाश सिंह, विजय प्रकाश मिश्र, मेवालाल यादव सहित दर्जनों समर्थकों ने उपस्थित होकर आन्दोलन को अपना समर्थन दिया।

सड़क दुर्घटना मे महिला की मौत

बदलापुर जौनपुर |स्थानीय तहसील क्षेत्र के खुर्द गांव निवासी 28 वर्षीय संजू प्रजापति की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि संजू बाइक से दवा लेने के लिए जौनपुर जा रही थीं। इसी दौरान एनएच-731 पर बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने घायल महिला को उपचार के लिए नौपेंड्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद संजू को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। संजू की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके दो छोटे बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। हादसे को लेकर स्थानीय लोगों में सड़क की स्थिति और हाईवे पर बने गड़कों को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।

एनएच-233 चौड़ीकरण से प्रभावित किसानों की समस्याएं सुनकर डीएम ने दिए भुगतान के निर्देश



जौनपुर | केराकत तहसील क्षेत्र में एनएच-233 के चौड़ीकरण से प्रभावित 20 गांवों के किसानों को प्रतिकर धनराशि का शीघ्र भुगतान कराने की कवायद तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन.के. ने बुधवार को प्रभावित किसानों से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनीं और प्रतिकर भुगतान से जुड़े मामलों की जानकारी ली।जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित प्रकरणों का नियमानुसार त्वरित निस्तारण करते हुए पात्र किसानों को प्रतिकर धनराशि का भुगतान जल्द सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने किसानों से अपना बैंक खाता विवरण, फोटो, शपथ पत्र समेत अन्य आवश्यक अभिलेख संबंधित कार्यालय में शीघ्र उपलब्ध कराने की अपील की, ताकि भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो।इस दौरान डीएम ने एनएच-233 के चौड़ीकरण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य का नियमित निरीक्षण करने, कार्य में तेजी लाने तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए प्रतिकर भुगतान से संबंधित लंबित मामलों का नियमानुसार त्वरित निस्तारण किया जाए। साथ ही चौड़ीकरण कार्य में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न होने पाए।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह, उपजिलाधिकारी केराकत, एनएचएआई के परियोजना निदेशक समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

जय मां शारदा।

शुक्ला मैरिज हॉल

मिर्जापुर रोड मरियाहू रोड जौनपुर

बृंदावन पैलेस एवं मैरिज हॉल शादी

विवाह इगेजमेंट बरंडे पार्टी मीटिंग

एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें एक बार सेवा का अवसर दीजिए

जयेंद्र कुमार शुक्ला मुन्ना शुक्ला

(प्रोपराइटर)

मो.न. 9838998491,

9793787559, 8840610896

वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञान प्रकाश सिंह की अनूठी धार्मिक पहल पत्रकारों ने देखी बाबा नीब करौली के जीवन पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’

जौनपुर। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं समाजसेवी ज्ञान प्रकाश सिंह ने जनपदवासियों को आध्यात्मिक चेतना, भक्ति और सेवा के भाव से जोड़ने की दिशा में एक अनूठी पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू किए गए ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत बुधवार को जौनपुर के डीडी प्लेक्स सिनेमा हॉल में पूज्य संत बाबा नीब करौरी महाराज के जीवन एवं उनके आध्यात्मिक विचारों पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ की विशेष नि:शुल्क स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। ज्ञान प्रकाश सिंह के सौजन्य से आयोजित इस विशेष प्रदर्शन में जनपद के वरिष्ठ पत्रकारों डिजिटल मीडिया प्रतिनिधियों और डिजिटल क्रिएटर्स ने फिल्म देखी। फिल्म की शुरुआत से



पहले सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा कि श्री बजरंग बली की प्रेरणा

रखना जरूरी है। श्री सिंह ने कहा कि एक सप्ताह तक डीडी प्लेक्स सिनेमा हॉल दो शो में लोगों को फिल्म दिखानी की व्यवस्था मेरे द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि इस विशेष स्क्रीनिंग का उद्देश्य केवल फिल्म प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूज्य बाबा नीब करौरी जी महाराज के जीवन से जुड़े भक्ति, सेवा, करुणा और मानवता के संदेश को समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचाना भी है।‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत देशभर में विभिन्न सेवा एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जौनपुर में आयोजित यह फिल्म स्क्रीनिंग भी इसी क्रम में लोगों को सेवा और सामाजिक सहभागिता के भाव से जोड़ने की पहल के रूप में सामने आई है।

नि:शुल्क नेत्र शिविर का आयोजन, 30 मरीज आपरेशन के लिए वाराणसी रवाना

300 से अधिक मरीजों की जांच, समाजसेवी विनय सिंह झगडु की पहल पर जरूरतमंदों को मिली राहत

मडियाहू जौनपुर। स्थानीय नगर पंचायत के खैरुद्दीनगंज स्थित टीचर्स कॉलोनी के पास जीआरसी कार्यालय पर बुधवार को आर जे शंकरा आई हॉस्पिटल, वाराणसी के सहयोग से नि:शुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों ने पहुंचकर आंखों की जांच कराई। जांच के बाद ऑपरेशन के लिए चयनित 30 मरीजों को नि:शुल्क बस से वाराणसी स्थित अस्पताल भेजा गया।

शिविर का शुभारंभ समाजसेवी विनय कुमार सिंह झगडु रामनगर ब्लॉक प्रमुख पति दयाराम पटेल और दिनकर इंटर कॉलेज जमालापुर के पूर्व प्रवधानाचार्य सूर्यभान सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। सुबह

से ही मडियाहू नगर क्षेत्र के साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों से मरीजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। चिकित्सकीय टीम ने मरीजों की आंखों की जांच कर आवश्यक परामर्श दिया।

शिविर में 200 से अधिक मरीजों का पंजीकरण कर नेत्र परीक्षण किया गया, जबकि आयोजकों के अनुसार कुल 300 से अधिक लोगों को जांच एवं चिकित्सकीय सुविधा का लाभ मिला। आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद मरीजों के लिए शिविर काफी उपयोगी रहा।

30 मरीज ऑपरेशन के लिए वाराणसी रवानाजांच के दौरान ऑपरेशन के लिए चयनित मरीजों को वाराणसी स्थित आरजे शंकरा

आई हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था की गई। दोपहर करीब एक बजे पहले चरण में 14 मरीजों को समाजसेवी विनय कुमार सिंह झगडु ने हरी झंडी दिखाकर नि:शुल्क बस से रवाना किया। इसके बाद करीब तीन बजे दूसरे चरण में 16 मरीजों को वाराणसी भेजा गया। इस तरह कुल 30 मरीज ऑपरेशन के लिए रवाना हुए।

जनप्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों की मौजूदगी

शिविर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामनगर एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव अरविंद सिंह मखड़ू चंद्रभान यादव प्रधान, अजय कुमार जायसवाल उर्फ बबलू, समर यादव, सभासद राकेश कुमार गुप्ता, रिस्कू आलोक कुमार सिंह, विनोद कुमार

सिंह उर्फ बच्चा समेत नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।उपस्थित लोगों ने जरूरतमंदों के लिए नि:शुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराने की पहल की सराहना की। चिकित्सकीय टीम को दी गई विदाई

शिविर के समापन पर समाजसेवी विनय कुमार सिंह झगडु ने आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल, वाराणसी से आए चिकित्सकों और सहयोगी स्टाफ के प्रति आभार जताया। चिकित्सकीय टीम में डॉ. गौरी, निलेश, रानी, गणेश समेत अन्य कर्मियों ने मरीजों की जांच और परामर्श में सहयोग किया। इसके बाद टीम को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई।

पेंशनर्स को हल्के में न ले सरकार मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन होगा तेज

जौनपुर। आठवें वेतन आयोग में जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनर्स को शामिल किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को जौनपुर में पेंशनर्स का आक्रोश खुलकर सामने आया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन के बाद आयोजित सभा में वक्ताओं ने केंद्र सरकार से पेंशनर्स के साथ कथित भेदभाव समाप्त करने की मांग की। सभा को संबोधित करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक ने सरकार को चेताते हुए कहा कि पेंशनर्स को हल्के में न लिया जाए। मोहकियों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो संगठन बड़े संघर्ष के लिए मजबूर होगा।पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर्स ने अपने सेवाकाल में पूरी निष्ठा के साथ सरकार और समाज की सेवा की है। सेवानिवृत्ति के बाद उनकी जायज मांगों की अनदेखी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आठवें वेतन आयोग के दायरे में पुराने पेंशनर्स को शामिल किए जाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। सरकार को पेंशनर्स की चिंताओं पर गंभीरता से विचार करते हुए पूर्व की



व्यवस्था के अनुरूप उन्हें भी वेतन आयोग की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए।उन्होंने कहा कि तिथि के आधार पर पेंशनर्स में विभेद की स्थिति पैदा होना चिंता का विषय है। सरकार को ऐसा कोई प्रावधान नहीं करना चाहिए जिससे एक ही वर्ग के पेंशनर्स के बीच अधिकारों को लेकर अंतर पैदा हो। उन्होंने केंद्र सरकार से पेंशनर्स की मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपेक्षा करते हुए कहा कि मांगों लंबित रहने पर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संगठन की रणनीति के अनुसार कदम उठाया जाएगा।कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित धरना-प्रदर्शन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सीबी सिंह ने की और संचालन

जिला मंत्री कृपाशंकर उपाध्याय ने किया। प्रदर्शन के दौरान पेंशनर्स ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए 12 सूत्रीय मांगों का प्रस्ताव पारित किया।

इनमें आठवें वेतन आयोग में जनवरी 2026 से पहले के पेंशनर्स को शामिल करना, वेतन आयोग की प्रक्रिया में विलंब होने पर अंतरिम राहत देना, कर्मचारियों-पेंशनर्स-शिक्षकों के लिए अलग सीपीआई निर्धारित करना, 65 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रत्येक पांच वर्ष पर पांच प्रतिशत पेंशन वृद्धि तथा 50 प्रतिशत से अधिक महंगाई भत्ते को मूल पेंशन में मर्ज करने जैसी मांगें प्रमुख रही।धरना स्थल पर पहुंचे शिक्षक या सख्त प्राधिकारी को देने की अपील की।अतिथियों ने बच्चों को सहायता के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए 1090, 1098 और 15100 के माध्यम से मदद लेने के लिए जागरूक किया।विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहम्मद नासिर खान ने अतिथियों का मार्त्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन धर्म ने किया, जबकि अंत मेंप्रधानाचार्य ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एडीजे द्वितीय के कार्यलय से सुनील कुमार मौर्य (ऑफेटर) और सुनील कुमार (पीएलबी) के अलावा विद्यालय के शाहिद अलीम, अनवर अल्वी, मो. अहमद, तंजील, रुशी, सलमान, आजम, अनुपम, सुशील, आतिश, मो. अली, शहजाद, जैस, फैजी, प्रदीप सहित अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से लैंगिक अपराध पर पाक्सो एक्ट में कठोर सजा का प्रावधान

जौनपुर। मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज में जनपद न्यायाधीश जौनपुर श्री सुशील कुमार शशि के निर्देशन में विधिक सक्षमता शिविर के तहत पॉक्सो एक्ट-2012 को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को बाल संरक्षण और लैंगिक अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। मुख्या अतिथि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्री उमेश कुमार तथा चीफ लीगल एड डिप्टिस काउंसिल (एलएडीसी) श्री अनिल कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से संबंधित लैंगिक अपराधों के मामलों में पॉक्सो एक्ट के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने विद्यार्थियों को अधिनियम की विभिन्न धाराओं और बच्चों के अधिकारों के बारे में विस्तार से

बताया।उन्होंने कहा कि बच्चों के प्रति गलत नीयत से किया गया अनुचित स्पर्श लैंगिक उत्पीड़न तथा अन्य यौन अपराध कानून के दायरे में आते हैं। नाबालिग बच्चों से संबंधित मामलों में कानून की जानकारी होना और किसी भी अनुचित घटना की स्थिति में तत्काल विक्ससनीय व्यक्ति या संबंधित हेल्पलाइन से सहायता लेना बेहद जरूरी है।कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बताया गया कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध की प्रकृति और संबंधित धारा के आधार पर कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें गंभीर मामलों में लंबी अवधि की सजा से लेकर आजीवन कारावास तथा कुछ अपराधों में मृत्युदंड तक का प्रावधान है। अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं से किसी भी प्रकार की अनुचित घटना को छिपाने के बजाय तत्काल इसकी जानकारी अभिभावक,

शिक्षक या सख्त प्राधिकारी को देने की अपील की।अतिथियों ने बच्चों को सहायता के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए 1090, 1098 और 15100 के माध्यम से मदद लेने के लिए जागरूक किया।विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहम्मद नासिर खान ने अतिथियों का मार्त्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन धर्म ने किया, जबकि अंत मेंप्रधानाचार्य ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एडीजे द्वितीय के कार्यलय से सुनील कुमार मौर्य (ऑफेटर) और सुनील कुमार (पीएलबी) के अलावा विद्यालय के शाहिद अलीम, अनवर अल्वी, मो. अहमद, तंजील, रुशी, सलमान, आजम, अनुपम, सुशील, आतिश, मो. अली, शहजाद, जैस, फैजी, प्रदीप सहित अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

नगर मजिस्ट्रेट महिपाल सिंह ने संगठन का ज्ञापन प्राप्त किया और उसे प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री तक भेजने का आश्वासन दिया।

सभा में इंजीनियर प्रमोद कुमार सिंह, दशरथ राम, चंद्रशेखर सिंह, रामकृष्ण यादव, ओमकार नाथ मिश्र, नरेंद्र कुमार सिंह, पुट्टीलाल यादव, सूबेदार यादव, राजेश कुमार श्रीवास्तव, मनीरेवी, महालक्ष्मी वर्मा, कांति सिंह, नंदलाल सरोज, गोरखनाथ माली, राजेंद्र प्रसाद सिंह, अशोक कुमार मौर्य, कंचन सिंह, विजय कुमार, वाईएसएन सिंह, शंभूनाथ, रामप्रताप यादव, प्रेमधर उपाध्याय, कामरुद कल्लू, रवींद्र सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, बीडी सिंह, अवधेश कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, विनय कुमार गुप्ता, डॉ. आशापाम यादव, साहबाल यादव और नरेंद्र त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

.नोटिस

हेतु संदर्शित करने की सूचना (साधारण प्रारूप)

न्यायालय सिविल जज जूडि0 शाहगंज जौनपुर।

वाद सं0-752 / 2025

मुन्नर प्रसाद-बनाम-रामचन्द्र

1.रामचन्द्र पुत्र मोतीलाल नि0ग्रा0 असरफपुर (उसरहट0) पर0 अंगुली तह0 शाहगंज जिला जौनपुर 2.विकासचन्द पुत्र रामचेत नि0ग्रा0 कौडिया पर0 अंगुली तह0 शाहगंज जिला जौनपुर।

ता0पेशी-04.11.2026 आपति व निस्तारण

चूँकि उपर नामांकित न इस न्यायालय मे आवेदन किया है अतएव आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उक्त आवेदन के खिलाफ आपति करने के लिये दिनांक 04.11.2026 आपति व निस्तारण दिवस का अपराह्न स्वयं या सम्पर्क रुपेण अपने अधि वक्ता द्वारा हाजिर हो। ऐसा करने मे असफल रहने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय सुना और अवधारित किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर सहित दिवस 2026ई0 को निकाली गई।

आज्ञा से सिविल जज जूडि0 शाहगंज जौनपुर।

जिलाधिकारी ने कोषागार का किया भौतिक सत्यापन, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

जौनपुर। वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-2 के अपेन्डिक्स-20 में वर्णित प्रावधानों के क्रम में जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. ने बुधवार को कोषागार का भौतिक सत्यापन किया। वित्तीय वर्ष के छह माह के अंत में 30 सितंबर एवं 31 मार्च को कोषागार के भौतिक सत्यापन का प्रावधान है।



जिलाधिकारी ने कोषागार के डबल लॉक में सुरक्षित जनरल स्टाम्प, अधिवक्ता कल्याणकारी स्टाम्प, कोर्ट फीस, नोटोरियल स्टाम्प, बहुमूल्यक आदि का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान उन्होंने कोषागार की व्यवस्थाओं और अभिलेखों का भी जायजा लिया।उन्होंने कोषागार के पेंशन कक्ष एवं पेंशन संबंधी पत्रावलियों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक जानकारी प्राप्त की। साथ ही कोषागार के कर्मचारियों तथा वहां मौजूद पेंशनरों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ कोषाधिकारी उमाशंकर यादव, सुरेश सिंह यादव, पवन, रमेश सरोज सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मिशन शक्ति टीम द्वारा पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद व मतभेद को आपसी समझौता एवं काउंसलिंग के माध्यम से सुलझाया

जौनपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा दोनों पक्षों को काउंसलिंग के माध्यम से



गैशक के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा क्षेत्राधिकारी मडियाहू के पर्येक्षण में प्रमारी निरीक्षक मडियाहू के नेतृत्व में थाना मडियाहू मिशन शक्ति टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 50 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण सुझा एवंआत्मनिर्भता को बढ़ावा देने हेतु दिनांक-29092026 को मिशन शक्ति फेज-50 अभियान के तहत प्रथम पक्ष नाजिया फखीन द्वितीय पक्ष मेहमूद सूरफियान निवासीगण ग्राम गल्ली मेहमूद थाना मडियाहू जनपद जौनपुर दोनों पक्षों में आपस मे आपसी मतभेद को लेकर विवाद था जिसमें जांच के क्रम मेंउभय पक्षों को मिशन शक्ति केंद्र पर बुलाया गया। उभय पक्षों की उपस्थित मेंदोनोंपक्षों की बातेंसुनी गई व समझी गई

समझाया बुझाया गया तथा उभय पक्षों की आपसी सहमति से सुलह-समझौता किया गया मिशन शक्ति टीम का विवरण प्रमारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र थाना मडियाहू जौनपुर 2 मिशन शक्ति टीम प्रमारी अपरध 1 निरीक्षक इरफान अली मडियाहू जौनपुर 3 रि0 म0 आ0 खुशी यादव थाना मडियाहू जौनपुर 4 रि0म0आ0 प्रीती थाना मडियाहू जौनपुर

सम्मन

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय सिविल जज जूडि0 शाहगंज जौनपुर।

वाद सं0-752 / 2025

मुन्नर प्रसाद-बनाम-रामचन्द्र

1.रामचन्द्र पुत्र मोतीलाल नि0ग्रा0 असरफपुर (उसरहट0) पर0 अंगुली तह0 शाहगंज जिला जौनपुर 2.विकासचन्द पुत्र रामचेत नि0ग्रा0 कौडिया पर0 अंगुली तह0 शाहगंज जिला जौनपुर।

ता10पेशी-04.11.2026

जवाबदेही व तनकीह

हरगाह ने आपके नाम एक नालिश बावतके दायरकी है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 04.11.2026 जवाबदेही व तनकीह बवक्त बजे अदालत या मारफत अपने वकील के जो मुकदमा के हालात से करार वाकई वाकिब हो और कुल उमूरत अहम मुकलिका मुकदमा का जवाब दे सके या मय ब्याज हेतु।

चूँकि उक्त ने प्रमाण-पत्र की अभिप्राप्ति के लिये आवेदन किया है और तारीख 13.10.2026 ई0 वास्ते आपतिर्धनिस्तारण के सुनवाई के लिए नियत हुआ है।

अत यह उद्घोषणा की जाती है कि जिस किसी को आवेदन के सम्बन्ध में आपति हो वह स्वयं या किसी वकील द्वारा उक्त न्यायालय में नियत तिथि पर उपस्थित होकर आपति पेश करे। ऐसा करने से असफल रहने पर एक पक्षीय सुना व अवधारित किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर सहित दिनांक 2026ई0 को निकाली गई।

आज्ञा से सिविल जज जूडि0 शहर जौनपुर।